A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2024

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-50 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

जलवायु परिवर्तन भारतीय सेना के लिए बड़ा मसला क्यों नहीं?

मनोज नरवणे

जलवायु को लेकर अपनी तरह का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन 'क्लाइमेट वीक' 22 से 29 सितंबर तक न्यूयॉर्क सिटी में मनाया गया। यह समारोह संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र और न्यूयॉर्क की भागीदारी से हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जब दुनिया भर के नेता इकट्ठा होते हैं उसी दौरान इसे भी मनाया जाना जलवायु परिवर्तन और दुनिया पर इससे पड़ने वाले प्रभावों की अहमियत को रेखांकित करता है।

अगला जो आयोजन होने वाला है वह है - यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 'सीओपी 29', जो इस साल नवंबर में अज़रबैजान के बाकू में होगा। ओज़ोन की छीजती परत और समुद्र के ऊंचे उठते स्तर तथा इनके वैश्विक प्रभावों आदि पर तो बराबर चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के समीकरण पर क्या असर पड़ता है, इस पर काफी कम चर्चा की जाती है।

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनियाभर में सैन्य कार्रवाईयों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। धरती का तापमान बढ़ते ही बर्फ की चोटियां पिघलने लगती हैं, जलस्तर बढ़ने लगता है, और बिन मौसम घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसे में सेनाओं को पारंपरिक खतरों से बिल्कुल अलग कार्रवाई के नए परिदृश्य के लिए खुद को तैयार रहना चाहिए। सामयिक बने रहने के लिए सैन्य योजनाकारों को इस बात का विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन रणनीति, कार्रवाई और सामरिक स्तरों को किस तरह प्रभावित करता है, संसाधन के आवंटन के लिए क्या चुनौतियां पेश करता है और सैन्य नियोजन में नयापन लाने की जरूरत को रेखांकित करता है।

जलवायु परिवर्तन सैन्य कार्रवाइयों को सबसे पहले तो भू-राजनीतिक समीकरण को बदलकर प्रभावित करता है। जलवायु से संबंधित आपदाएं बढ़ती हैं तो देश के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जल संकट, खाद्य सामग्री की कमी और लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवासन संघर्षों को जन्म दे सकता है जिसके चलते सेना को मानवीय सहायता और आपदा राहत की कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं। 'फोर्स मल्टीप्लायर' की तरह जलवायु परिवर्तन सेना के लिए खतरा 'मल्टीप्लायर' बन जाता है, जो पहले से विस्फोटक क्षेत्रों में तनाव को और बढ़ा देता है। यह मुहावरा 'इन्टरनेशनल मिलिटरी काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज ऐंड सिक्यूरिटी' के महासचिव शेरी गुडमैन ने गढ़ा था।

मानवीय संकटों के अलावा, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नई रणनीतिक चुनौतियां पेश करता है, मसलन आर्कटिक सागर का पिघलना। बर्फ के सिकुड़ने से जहाजों की आवाजाही के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे अछूते प्राकृतिक संसाधनों के तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस परिवर्तन से अमेरिका, रूस और चीन के बीच होड़ और बढ़ेगी। तमाम देश इस क्षेत्र में अपना पैर जमाने पर आमादा हैं। इसी तरह, धरती का तापमान बढ़ने से भारतीय सैन्य योजनाकारों को 'केंपेनिंग सीजन' की अवधारणा पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, जिसे रणनीति तथा कार्रवाई के स्तरों पर सुरक्षा समीकरण का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ठंड का हल्का मौसम और हिमपात में कमी लाभकारी भी हैं और नुकसानदायक भी।

बढ़ता तापमान और बढ़ती नमी सैनिकों को थका सकती है जिससे ट्रेनिंग और तैनाती के दौरान उनकी क्षमता घट सकती है। पहले से ही कम संसाधन को अगर आपदा में मानवीय राहत मिशन पर खर्च करना पड़ा तो सैन्य ऑपरेशन्स के मामले में कटौती करनी पड़ेगी। तूफान, बाढ़, जमीन धंसने, और जंगल में आग लगने से सैन्य ठिकानों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को खतरा पहुंचता है। खतरनाक इलाकों में स्थित सैन्य अड्डों के नष्ट होने का खतरा रहता है जिससे सेना की तैयारी और संसाधन आवंटन पर असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन जब संसाधन के आवंटन को प्रभावित करता है तब साजो-सामान से संबंधित चुनौतियां भी उभरती हैं। सैन्य कार्रवाई सप्लाई चेन की निरंतरता पर निर्भर करती है और जलवायु के कारण पैदा होने वाली अड़चनों से इस निरंतरता को खटर पहुंचता है। बाढ़ या हिमस्खलन से परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं नष्ट हो सकती हैं जिससे सेना और सप्लाई का स्थानांतरण मुश्किल हो सकता है। मौसम से संबंधित बड़ी घटनाएं जब बार-बार घटने लगी हैं, सेना के योजनाकारों को साजो-सामान से जुड़ी रणनीति में इनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से खासकर पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों की कमी पड़ सकती है।

सैन्य कार्रवाइयों में संसाधन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और स्वच्छ जल और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों की कमी इन कार्रवाइयों को बुरी तरह बाधित कर सकती है। सेना को कार्रवाई के लिए तैयार रहने और मजबूत बने रहने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और टिकाऊ तौर-तरीकों को अपनाना होगा। यह परिवर्तन पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं उपयुक्त नहीं है बल्कि यह कमजोर सप्लाई और संसाधनों पर निर्भरता को घटाकर कार्रवाई संबंधी सुरक्षा में इजाफा करता है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना अपने अड्डों के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग और फॉसिल ईंधन के उपयोग में कटौती करने और फॉसिल फ्यूल की गुंजाइश की जांच कर रही है। ऊर्जा भंडारण में नए प्रयोग और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से कार्यकुशलता बढ़ेगी और ऊर्जा आपूर्ति में बाधाओं को कम किया जा सकेगा। हमारे सीमावर्ती इलाकों में डीजल जेनरेटर की जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इस दिशा में एक कदम है - यह परिवहन के लिए फ्यूल की लागत को कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। सैन्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा का यह मेल ही आगे ले जाने वाला कदम है।

निर्णय प्रक्रिया में जलवायु संबंधी जोखिम का ध्यान भी रखने के लिए जलवायु संबंधी समग्र रणनीति की ज़रूरत होगी। सड़क परिवहन और हाइवे मंत्रालय के साथ सलाह-मशविरा सेना को अपने वाहनों के विशाल बेड़े के लिए फॉसिल फ्यूएल की जगह 'ग्रीन इनर्जी' अपनाने का रास्ता बनाएगा। भारतीय वायुसेना एंटोनोव एएन-32 ट्रांसपोर्ट विमान को 10 फीसदी ब्लेंडेड बायोडीजल के उपयोग से उड़ाने का परीक्षण कर रही है। इस ईंधन का हेलिकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों समेत सभी विमानों में इस्तेमाल करने की योजना है। जलवायु परिवर्तन का मसला राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करता है। सैन्य कार्रवाइयों के लिए दूसरे देशों, एनजीओ और मानव सेवा संगठनों के साथ सहयोग की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। आपदा में बहुराष्ट्रीय कार्रवाई से मित्र देशों की सेना के साथ सहयोग का रिश्ता बनाने में और जलवायु से संबंधित संकटों के खिलाफ तेज़ी से और प्रभावी कदम उठाने में मदद मिल सकती है। जलवायु से संबंधित ऐसी गैर-पारंपरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना को सक्रिय योजना और टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ेगा। यह सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बुनियादी पहलू बन गया है।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं
वो रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं
इक तुम हो कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती
इक हम हैं कि हर शोर से उकताए हुए हैं
दो चार सवालात में खुलने के नहीं हम
ये उक़दे तेरे हाथ के उलझाए हुए हैं
अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे
हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए हैं
हर बात को बेवजह उदासी पे ना डालो
हम फूल किसी वजह से कुम्हलाए हुए हैं
कुछ भी तेरी दुनिया में नया ही नहीं लगता
लगता है कि पहले भी यहां आए हुए हैं
है देखने वालों के लिए और ही दुनिया
जो देख नहीं सकते वो घबराए हुए हैं
सब दिल से यहां तेरे तरफ़दार नहीं हैं
कुछ सिर्फ़ मिरे बुग्ज़ में भी आए हुए हैं।

- फ़रीहा नक़वी

माईनिंग कॉन्क्लेव शुरुः मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर उद्योग और पर्यटन के बाद खनिज क्षेत्र में हुई कॉन्क्लेव

मिनरल रिसोर्सेस में नम्बर वन है मध्यप्रदेश

- प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, एनर्जी सरप्लस स्टेट
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में अग्रणी
- भोपाल में दो दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ
- देश-विदेश के निवेशक हुए शामिल

निवेश के मुख्य आकर्षण

- आगामी 200 वर्ष के लिए कोयल का रिजर्व भंडार
- सरप्लस बिजली और पानी वाला राज्य
- बेहतर कनेक्टीविटी के लिए सड़कों का जाल
- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में अग्रणी
- श्रम कानून इंडस्ट्रीज फ्रेंडली
- प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता
- निवेशकों के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम
- उद्योगों में नो मैन डे लॉस
- ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम
- लोक सेवाओं की गारंटी के लिए अधिनियम लागू
- मैगनीज एवं कॉपर अयस्क उत्पादन में देश में प्रथम
- रॉक फॉस्फेट में देश में दूसरे स्थान पर
- चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर

म.प्र. में निवेश कर, प्रदेश तथा देश की विकास यात्रा में बनें सहभागीः मुख्य सचिव श्री जैन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने आईएटीओ का अधिवेशन हुआ।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर भोपाल में दो दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में प्रदेश की खनिज संपदा की विस्तार से जानकारी दी जाकर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि प्रदेश में खनिज की प्रचुर मात्रा होने और राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

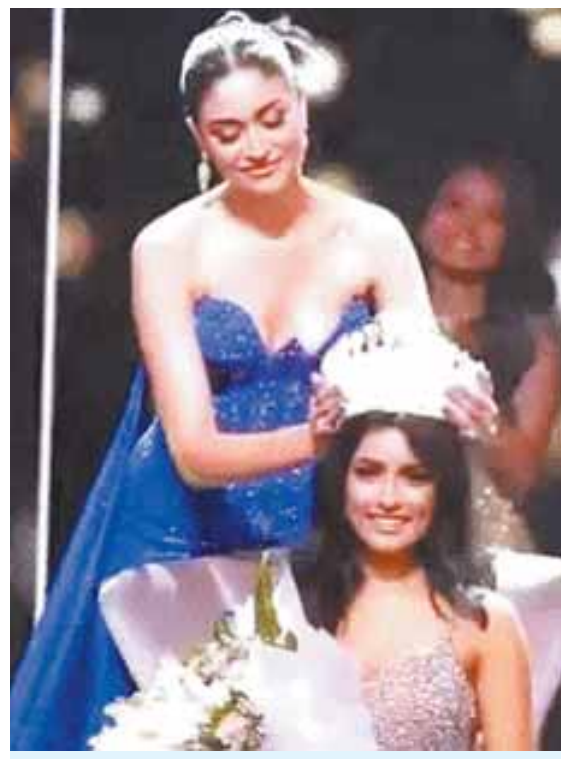

देश के मध्य में होने से यहाँ पहुँचना आसान- भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में गुरूवार को 2 दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने किया। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश का तेजी से विकसित होता राज्य है। प्रदेश मिनरल रिसोर्सेस में तो नम्बर वन है ही, यहां पानी, कोयला एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी प्रचुरता है।

(शेष पेज-3 पर)

म.प्र.की निकिता पोरवाल बनीं मिस इंडिया-2024

मिस वर्ल्ड में करेंगी 'इंडिया' को रिप्रेजेंट

उज्जैन (नप्र)। मध्यप्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल ने बुधवार रात फेमिना मिस इंडिया-2024 का खिताब जीत लिया है। निकिता अब मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वर्ली में आयोजित किया गया था। निकिता को मिस इंडिया का खिताब मिलने के बाद उनके अरविंद नगर स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

करीब दो माह पहले ही शहर की निकिता पोरवाल ने 200 प्रतिभागियों के बीच फेमिना मिस इंडिया मध्यप्रदेश-2024 का खिताब जीता था। उन्होंने पहली बार किसी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और उसमें वे सिलेक्ट हुई थीं। निकिता को एक्टिंग के अलावा लिखने का भी शौक है। निकिता कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज ड्रामा की स्क्रिप्ट लिख चुकी हैं। उनके लिखे ड्रामा में 250 पेज की कृष्ण लीला भी है। ये पहली बार है, जब मध्यप्रदेश से किसी ने मिस इंडिया का खिताब जीता है।

निकिता की फिल्म 'चंबल पार' का ट्रेलर आ चुका है- निकिता का अपकमिंग प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। फिल्म का टाइटल 'चंबल पार' है। निकिता की बहन वैशाली जैसवाल इंदौर में सीए हैं, एक भाई प्रद्युम्न पोरवाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इंजीनियर।

'फैमिना मिस इंडिया-2024' का खिताब जीतने पर मुख्यमंत्री ने बेटी निकिता को दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल को 'फेमिना मिस इंडिया-2024' का खिताब जीतने पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लिखा है कि बेटी निकिता 'मिस वर्ल्ड पेजेंट' में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का मान बढ़ाएं यही कामना है।

म.प्र.में 20 से बढ़ेगी ठंड

- पचमढ़ी में दिन का तापमान 26 डिग्री तक पहुंचा, भोपाल समेत कई जिलों में धूप निकली

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश से मानसून विदा हो गया है लेकिन 3 सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगले कुछ दिन बूंदाबांदी और बादल वाला मौसम बना रहेगा। 20 अक्टूबर से ठंड का असर बढ़ेगा। तेज ठंड नवंबर की शुरुआत में दिखेगी। हालांकि, गुरुवार की सुबह से भोपाल समेत कई जिलों में धूप निकली है। इससे पहले बुधवार को बैतूल, छिंदवाड़ा और बुरहानपुर में बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र प्रेशर एरिया (डिप्रेशन) आगे बढ़ रहा है। वहीं, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव हैं। इस वजह से प्रदेश में बूंदाबांदी होगी और बादल छाए रहेंगे।

तेज बारिश में बह गई उपज- बुधवार को बैतूल के शाहपुर में आधा घंटा मूसलाधार बारिश हुई। मंडी में उपज बेचने आए किसानों का कई क्विंटल अनाज पानी में बह गया। कई किसानों की उपज भीग गई। छिंदवाड़ा के दमुआ में नदी के बीच उफनते पानी में दो युवतियां फंस गई। नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से ऐसा हुआ।

बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र के मोहद गांव से सटे वन क्षेत्र में बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण धोरक नाले में बाढ़ आ गई। 15-20 मजदूर नाले के दूसरी ओर फंस गए। गांव के युवाओं ने उन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बैतूल की शाहपुर मंडी में उपज बेचने आए किसानों का अनाज तेज बारिश में बह गया।

कई जिलों में तेज धूप

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम खुला रहेगा। गुरुवार को कई जिलों में तेज धूप निकली। भोपाल में भी आसमान साफ रहेगा। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

बेंगलुरु टेस्ट में रोहित सेना का शर्मनाक रिकॉर्ड

5 बल्लेबाज नहीं खोल सके खाता, भारत 46 रनों पर ढेर

5 शून्य पर आउट हुए

- 9 बल्लेबाज ऐसे रहे जो दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके
- भारत का अपनी सरजमीं पर सबसे शर्मनाक प्रदर्शन

बेंगलुरु (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गुरुवार किसी बुरे सपने की तरह रहा। उसे बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 46 रनों पर ढेर कर दिया है। यह उसका भारत में खेले गए किसी भी टेस्ट में सबसे छोटा स्कोर है, जबकि ओवर ऑल तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्षाबाधित पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने लंच तक छह विकेट 34 रन पर गंवा दिए थे, जबकि इसके बाद पंत आउट हुए और फिर टीम लगातार विकेट गंवाती रही। रोचक बात यह है कि न्यूजीलैंड ने इस पारी में सिर्फ 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और तीनों ही तेज गेंदबाज थे।

इससे पहले मैच के ऑफिशल दूसरे दिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो उनकी टीम के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। ओवरकास्ट कंडीशन में कीवी गेंदबाजों ने पहले ही घंटे में भारत के शीर्षक्रम की धज्जियां उड़ा दी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 36.3 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार,18 अक्टूबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

प्रतियोगिता में भाग लेने से मिलता है नया जोश और मनोबल : राज्यपाल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से नया जोश और मनोबल तो मिलता ही है, साथ ही अपने और दूसरों के प्रदर्शन के अनुभव से कौशल का नया स्तर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में ज्ञान और कौशल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हार-जीत से कही अधिक महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति, सुसंस्कृत जीवनशैली की गरिमा और गौरव का सम्मान है।

राज्यपाल श्री पटेल आज केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय क्रीड़ा, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्पर्धा, युवा महोत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विशिष्ट ग्रंथों, 'सर्वसमावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानन्द सरस्वती' और 'भारतीय ज्ञान परम्परा शिक्षक शिक्षा' का लोकार्पण किया। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, युव संसद जयपुर के संस्थापक श्री आशुतोष जोशी मंचासीन थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आधुनिक मानव जीवन से जुड़े क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी जीवन आदि कई विषयों में संस्कृत ज्ञान निधि की प्रासंगिकता आज बढ़ रही है।दुनिया में संस्कृत भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे प्रमुख ज़रिया है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक और शोध परक दृष्टि से देखा जाए और ज्ञान के नए स्वरूप को प्रकाशित किए जाए। समय की आवश्यकता है कि हमारे पास ऐसे युवा हो, जिनमें संस्कृत के साथ कम्प्यूटर कोडिंग की तकनीक और अनुसंधान का सामर्थ्य हो।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत निर्माण प्रयासों के लिए जड़ों से जुड़ें वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम युवाओं का निर्माण समय की जरूरत है। विश्वविद्यालय को संस्कृत भाषा की भारतीय ज्ञान परम्परा को भविष्य की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय से भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की जिम्मेदारी लेना होगी।

राज्यपाल केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्पर्धा के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुए

संक्षिप्त समाचार

राम माधव बनाए जा सकते हैं जम्मू-कश्मीर के एलजी

कई अन्य प्रदेशों में भी बदले जा सकते हैं गवर्नर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम माधव के नाम की चर्चा इन दिनों जोर-शोर से हो रही है। ऐसी चर्चा है कि उन्हें जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म है। राम माधव की कश्मीर मामलों पर गहरी समझ और अनुभव को देखते हुए, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ अन्य प्रदेशों में भी नए राज्यपालों की नियुक्तियां की जा सकती हैं। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। बुधवार को वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता भी संभाल ली।

शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया जारी

बढ़ेगा तनाव

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। शेख हसीना के अलावा 45 लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेता भी शामिल हैं। इस प्राधिकरण को शेख हसीना ने ही बनाया था ताकि साल 1971 में पाकिस्तानी सेना के नरसंहार में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। अब इसी प्राधिकरण का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करा दिया है। शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और अब बांग्लादेश की सरकार भारत से अवामी लीग की नेता को प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। मानवता के खिलाफ अपराध में कनेक्शन है।

एक करोड़ की ईनामी महिला नक्सली सुजाता गिरफ्तार

बस्तर में हमलों की है मास्टरमाइंड

रायपुर/सुकमा (एजेंसी)। तेलंगाना पुलिस ने एक करोड़ की इनामी महिला नक्सली कल्पना उर्फ सुजाता (60) को गिरफ्तार किया है। वो हैदराबाद के महबूब नगर में इलाज कराने आई थी। नक्सली सुजाता छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में 100 से अधिक वारदातों में शामिल रही है। पुलिस ने बताया कि कल्पना उर्फ सुजाता पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इनाम था। उससे पूछताछ में नक्सलियों से बड़ा इनपुट मिल सकता है। सुजाता ने खुंखार नक्सली हिडमा को भी ट्रेनिंग दी है। साथ ही कई महिला नक्सली संगठन तैयार किए हैं। हालांकि बस्तर पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।

देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना

● सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को भेजी सिफारिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कर दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को भेजी अपनी सिफारिश में कहा है कि देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। बता दें कि वर्तमान सीजेआई 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। परंपरा के अनुसार सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है, जिसके चलते उन्होंने सीजेआई के पद के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना वरिष्ठता सूची में पहला नाम है।

बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर

● नेपाल बॉर्डर पर सरफराज और तालिब को मारी गई गोली

● दोनों की हालत गंभीर,रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी हैं

बहराइच (एजेंसी)। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और तालिब का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। शुरुआती जानकारी में सरफराज के मौत की खबर आ रही है। जबकि तालिब के पैर में गोली लगी है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का दूसरे नंबर का बेटा है। एक दिन पहले उसकी गोली चलाते हुए तस्वीर भी सामने आई थी। आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन, दोनों को कोतवाली नानपारा क्षेत्र में हांडा बसेहरी नहर के पास पुलिस ने घेर लिया। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार आज सुबह एक बयान जारी किया था। उसने कहा, मेरे भाई सरफराज, फहीम को एसटीएफ ले गई।

कांग्रेस विधायक के बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस सनातन को समाप्त करने की मानसिकता पर काम कर रही

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूसिंह जंडेल द्वारा भगवान शंकर के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक बाबूसिंह जंडेल द्वारा भगवान शंकर के बारे में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, गालियां दी गई हैं, उससे एक बार फिर यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी देश में सनातन को समाप्त करने की मानसिकता से काम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद शर्मा ने कहा कि किसानों से कर्जमाफी के झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों को 15 महीने सिर्फ छलने का कार्य किया। एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया। किसानों को छलने वाले वही कांग्रेस नेता आज किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते बैतूल के मुलताई में निर्दोष किसानों पर गोलियां चलवाने वाले दिग्विजय सिंह आज बहरूपिया बनकर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, जो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। किसान विरोधी नेता दिग्विजय सिंह समझ लें कि मध्यप्रदेश में अन्नदाता के लिए किसी भी तरह की खाद की कमी नहीं है। सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करा रही है और डीएपी में सब्सिडी भी बढ़ाई गयी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बाबूसिंह जंडेल ने जिस तरह भगवान शंकर के प्रति गालियों का प्रयोग किया है, उसके बारे में मैं राहुल गांधी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने मोहब्बत की दुकान खोली है या गालियों की? श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने भगवान शंकर के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं पर चोट की है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। कुछ मीडिया प्रतिनिधियों ने जब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सनातन को खत्म करना और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करना ही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है।

नायब सिंह सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के सीएम

● कुल 13 मंत्री बनाए गए,इनमें 6 पहले भी मंत्री रहे ● सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे शामिल,2 महिलाएं

पंचकूला (एजेंसी)। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली। जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से एक-एक मंत्री बनाया गया है। नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी पहले मंत्री रह चुके हैं।

अहीरवाल से नरबीर सिंह और आरती राव को मिली जगह

बीजेपी ने उसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट देने वाले अहीर यानी यादव समुदाय को भी पूरा सम्मान दिया है। अहीरवाल में पड़ने वाली 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को चुनाव में जीत मिली है। पार्टी ने गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट से चुनाव जीते राव नरबीर सिंह और महेंद्रगढ़ जिले की अटेली सीट से चुनाव जीतीं आरती सिंह राव को मंत्री बनाया है। राव नरबीर सिंह 2014 में भी मंत्री बने थे। आरती सिंह राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं।

जाट समुदाय को भी पार्टी ने दिया बराबर का महत्व

बीजेपी ने सैनी कैबिनेट में जाट समुदाय से आने वाले जिन दो नेताओं को मंत्री बनाया है, उनके नाम महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी हैं। महिपाल ढांडा पानीपत जिले की ग्रामीण सीट और श्रुति चौधरी भिवानी जिले की तोशाम सीट से चुनाव जीती हैं। श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक बाद बीजेपी में शामिल हुई थीं। राजपूत समुदाय को भागीदारी देते हुए यमुनानगर जिले की रादौर सीट से चुनाव जीते श्याम सिंह राणा को बीजेपी ने मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। फरीदाबाद सीट से चुनाव जीते विपुल गोयल सैनी कैबिनेट में वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पंजाबी समुदाय से आते हैं अनिल विज

नायब सिंह सैनी के बाद अनिल विज ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज सात बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार अंबाला जिले की अंबाला कैंट सीट से विधायक चुने गए हैं। अनिल विज खुद भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे लेकिन पार्टी नेतृत्व ने चुनाव के दौरान ही साफ कर दिया था कि सरकार बनने की सूरत में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पंजाबी समुदाय से आने वाले विज पार्टी के बड़े चेहरे हैं। बताना होगा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकूला के साथ ही सिरसा जिले में भी पंजाबी समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है। ऐसे में पार्टी ने अनिल विज को फिर से मंत्री बनाया है।

अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध

सीजेआई बोले-

● यह राजनीतिक समाधान था,जो कानून बना ● जस्टिस सूर्यकांत बोले-जियो और जीने दो,यह अच्छा निर्णय

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित चार जजों ने सहमति जताई है। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई। दरअसल, सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6ए को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं।

बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 लोगों की मौत

सीवान और सारण में 40 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई

छपरा (एजेंसी)। बिहार के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह सीवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई। सीवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन ने 24 मौत की पुष्टि की है। सीवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। सारण में जिनकी मौत हुई है, उन सभी ने 15 अक्टूबर को शराब पी थी। 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सीवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीवान सदर अस्पताल में भर्ती है। सारण से कुछ लोगों को पटना के पीएमसीएच भेज दिया गया है। सीएम नीतिश कुमार ने शराबकांड पर समीक्षा की है। डीजीपी को पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग करने को कहा है। साथ ही मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लेकर सभी पहलुओं पर जांच करें। पुलिस के अनुसार, कई लोगों ने 13 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में बिक रही पाउच वाली शराब पी थी। वहीं, एक सप्लायर ने शराब बेची थी।

आरक्षित टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे लाया नया नियम

● 120 दिन नहीं अब केवल 60 दिन पहले ही होगा रिजर्वेशन ● आईआरसीटीसी ने रिजर्वेशन के नियम में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने 120 दिन पहले टिकट बुक करने के नियम में बदलाव कर इसे 60 दिन कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह बदलाव 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इस फैसले के बाद अब यात्री अपनी यात्रा की तिथि से दो महीने पहले ही टिकट बुक करा सकेंगे। गुरुवार को रेल मंत्रालय की ओर से इसे लेकर जानकारी दी गई है। बता दें कि रेलवे तत्काल टिकट की व्यवस्था भी देता है। तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की तिथि से एक दिन पहले की जा सकती है। इसके लिए रोज सुबह 10 बजे के बाद 3 एसी लेकर ऊपर की श्रेणी के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है जबकि स्लीपर तत्काल बुकिंग सुबह 11 बजे से चालू हो जाती है। अगर किसी ने 1 नवंबर के बाद से टिकट पहले ही बुक कर लिए हैं तो रेलवे के इस फैसले का उन पर असर नहीं होगा। 1 नवंबर से जो यात्री टिकट बुक कराएंगे, उन पर ही यह फैसला लागू होगा। रेलवे ने विदेशी पर्यटकों को रिजर्वेशन में छूट दी है। वह 365 दिन पहले टिकट बुक करा सकेंगे।

डीजे पर डांस करते समय गिरा 5वीं का छात्र, मौत

मां मदद के लिए चिल्लाती रहीं; परिवार का आरोप-तेज आवाज से गई बच्चे की जान

भोपाल (नप्र)। भोपाल में डीजे की तेज आवाज से एक 13 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। घटना 14 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। समर बिल्लौरे (13) मां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जा रहे चल समारोह में डीजे पर डांस कर रहा था।

परिवार का आरोप है कि जैसे ही डीजे का साउंड तेज हुआ समर बेहोश हो गया। मां मदद के लिए चिल्लाती रहीं, लेकिन डीजेवाले ने साउंड कम नहीं किया। उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गए। जहां उसकी मौत हो गई। समर सेंट जोसफ स्कूल में पांचवीं क्लास का छात्र था।

घटना के बाद भी डीजे बजना बंद नहीं हुआ परिवार के लोगों ने बताया कि चल समारोह में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। लोग घर के बाहर नाच रहे थे। समर भी तेज साउंड सुनकर वहां भीड़ में शामिल हो गया और नाचने लगा। जश्न के दौरान वह अचानक गिर गया। उसके आस-पास के लोग नाचते रहे। मां जमुना देवी मदद के लिए चिल्लाती रहीं। लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद भी डीजे वाले ने डीजे बंद नहीं किया।

भाई बोला, तेज साउंड करने के बाद हुआ बेहोश- समर के बड़े भाई अमन बिल्लौरे ने बताया कि घटना सोमवार शाम 8 से 9 बजे की है। डीजे दूर से आ रहा था तब तक उसका साउंड कम था, मगर यहां हमारे इलाके में आकर डीजे वाले ने साउंड बड़ा दिया। इसके बाद समर बेहोश हो गया और हम उसे पहले अक्षय अस्पताल और बाद में नर्मदा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिवार के लोगों ने इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। मृतक युवक के बड़े भाई ने बताया कि तेज साउंड के चलते समर की हुई मौत।

मां ने कहा-समर को पहले से थी हार्ट की समस्या- समर की मां क्षमा बिल्लौरे ने बताया कि समर घर के बाहर डांस कर रहा था। जब यह घटना हुई, उस समय किसी ने न तो डीजे को रोका और न ही किसी ने इस बारे में पूछा। बस कोई उसे गोद में उठाकर यहां दे गया। उसे हार्ट में पहले से दिक्कत थी, उसके हार्ट में छेद था, मगर इन दिनों वह पूरी तरह से फिट था। उसे कोई दिक्कत नहीं थी।

2 करोड़ की सरकारी जमीन से हटवाया कब्जा

1 हेक्टेयर जमीन पर बना रहे थे मकान; जेसीबी लेकर पहुंची टीम, गिराए पिलर

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बगरोदा गांव में गुरुवार को 1 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा हटवाया गया। जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। जमीन पर 6 महीने पहले कब्जा किया गया था, 1 महीने में मकान बनाने के लिए पिलर भी खड़े कर दिए गए। जिला प्रशासन के अफसरों ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की। हुजूर तहसीलदार नरेंद्र परमार ने बताया कि बगरोदा में मेन रोड के किनारे की जमीन पर गोवर्धन साहू, कमलेश सेन और पतिराम पटेल ने कब्जा कर रखा था। नींव बिछाने के बाद पिलर खड़े हो गए थे और

इस पर निर्माण किया जाने वाला था। दोपहर में यहां टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू की। एक घंटे में कब्जा हटा दिया गया।

जेसीबी लेकर पहुंचे अफसर

कार्रवाई करने के लिए अफसर जेसीबी लेकर पहुंचे। विवाद न हो, इसलिए पुलिस बल भी मौजूद था। हालांकि, विवाद जैसी स्थिति नहीं बनी और एक घंटे में कार्रवाई करके टीम लौट गई। एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

जेल भरो आंदोलन करेंगे अतिथि शिक्षक

रणनीति बनाने भोपाल में जुटे; नियमितिकरण की मांग

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक अब जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसकी रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को भोपाल में मीटिंग हुई। उनकी नियमितिकरण की मुख्य मांग है। वे पदाधिकारियों और अतिथि शिक्षकों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग भी करेंगे।

अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले भोपाल में 2 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन

हुआ था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। प्रदर्शन करने पर पुलिस ने संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पंवार, संगठन से जुड़े बीएम खान, मुकेश जोशी और संतोष के खिलाफ नामजद और करीब ढाई सौ अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी।

आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे- संगठन से जुड़े और अतिथि शिक्षक रविकांत गुप्ता ने बताया, नियमितिकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। इस विषय पर भी भोपाल में गुरुवार को होने वाली मीटिंग में चर्चा की जाने की संभावना थी। इसमें पूरे प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होकर चर्चा करेंगे।

माइनिंग कॉन्क्लेव में देशभर के औद्योगिक घरानों को बुलाया

600 कंपनियों को इन्विटेशन; रिलायंस, अडाणी, बिरला जैसे बड़े ग्रुप भी आएंगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में गुरुवार से दो दिन एमपी माइनिंग कॉन्क्लेव शुरु हो गई थी। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कॉन्क्लेव में देश भर के माइनिंग सेक्टर के इन्वेस्टर और दूसरे राज्यों के खनिज विभाग के अधिकारी शामिल हुए है। इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश की करीब 600 कंपनियां शामिल हो रही हैं। देशभर के बड़े औद्योगिक घरानों को बुलाया गया है।

कॉन्क्लेव सीएस अनुराग जैन, हाईड्रोकॉर्बन की डीजी पल्लवी जैन, मिनरल एक्प्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी इंद्रदेव नारायण, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, सीआईआई मप्र के चेयरमैन आशीष वैश्य मौजूद हैं। माइनिंग और जियोलॉजी सेक्टर के अनुभवी विशेषज्ञ ट्रिपल आईटी तिरुपति के अरुण, आईआईटी धनबाद के मो दानिश, धनबाद के सहाद्र सिंह, श्रवण कुमार सिंह, जियोलॉजी एक्सपर्ट आए हैं।

कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए खनिज विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ल ने कहा कि मप्र में पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स समिट होता है। इसमें सभी सेक्टर की बात होती है। लेकिन, बहुत सालों से देश में कुछ सेक्टर्स ने अपनी-अपनी एक प्रैक्टिस सेटअप की है। जैसे दिल्ली में ऑटो शो होता है, बैंगलोर में एग्जिबिशन होता है। वैसे ही मप्र माइनिंग के क्षेत्र में उभरता हुआ राज्य है। इसलिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिया कि माइनिंग के लिए

अलग से कॉन्क्लेव करें। जिससे माइनिंग सेक्टर में रोजगार और देश की जीडीपी को बढ़ाने की संभावनाओं पर बात हो।

देश का स्ट्रैटेजिक डिफेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के स्ट्रैटेजिक सेक्टर कहलाते हैं उनमें कैसे योगदान दे सकते हैं। जैसे ईवी के लिए बैटरी चाहिए, कॉपर, लीथियम की जरूरत है। इस प्रकार के सेक्टर में माइनिंग कैसे सहभागिता कर सकता है। इन सारे विषयों पर बात होगी।

कई विषयों पर होगा प्रेजेंटेशन- सिंगरौली जिले में सोने का भंडार मिला है। पहली बार मध्यप्रदेश में सोने की खदान आवंटित की गई है, साथ ही दूसरे खनिज जैसे- लाइमस्टोन, मैंगनीज, ग्रेफाइट, वैनेडियम के लिए भी निवेशकों को एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) आवंटित किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में फ्यूचर की संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।

सीएम यादव करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन

कॉन्क्लेव में मुख्य सचिव अनुराग जैन की-नोट पर जानकारी देंगे और मध्यप्रदेश के खनिज संसाधनों पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव के शुरुआती सत्र में खनिज संसाधन, निवेश के अवसरों, पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी जाएगी।

तकनीकी-सत्रों में खनन सुरक्षा, स्मार्ट तकनीक, डिजिटिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग के उपयोग पर चर्चाएं होंगी। ड्रोन तकनीक और खदानों के डिजिटल समाधान पर भी एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। प्लानिंग-सेशन में कोयला, ऊर्जा, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, मिनरल-बेनेफिकेशन और एम-सैंड जैसे सब्जेक्ट्स पर विचार-विमर्श होगा।

प्राइमरी सेशन में खनिज विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 पर जानकारी देंगे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर प्रजेंटेशन देंगे। भारत सरकार की हाइड्रोकार्बन महानिदेशक डॉ. पल्लवी जैन गोविल, पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा करेंगी। डेलॉयट के पार्टनर राजीव मैत्रा मध्यप्रदेश में खनिज क्षमता के उपयोग पर अपनी प्रस्तुति देंगे।

आयुर्वेद, उपचार की प्राचीन और कारगर पद्धति : श्रीमती गौर

भोपाल में बनाया जा रहा है विशेष औषधि पार्क : महापौर श्रीमती राय

भोपाल(नप्र)। आयुर्वेद उपचार की प्राचीन पद्धति है। यह वर्तमान में भी उपचार की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। यह बात पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कही। राज्यमंत्री श्रीमती गौर शरद पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या नगर दशहरा मैदान में आयोजित 34वें आयुर्वेदिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर को संबोधित कर रहीं थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि परमार्थ और परोपकार करनेवालों के साथ अपने आप लोग जुडते जाते हैं। उन्होंने कहा कि नाड़ी वैद्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन कर परोपकार का कार्य कर रहें हैं। श्रीमती गौर ने शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों से कहा कि हमें उपचार की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद पर विश्वास करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से रोगों का स्थाई समाधान होता है। श्रीमती गौर ने नागरिकों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मालती राय ने कहा कि आयुर्वेद से उपचार के लिए लगाया गया निःशुल्क शिविर सराहनीय है। उन्होंने बताया कि भोपाल में विशेष औषधि पार्क बनाया जा रहा है। महापौर श्रीमती राय ने कहा कि भोपाल के 150 मंदिरों के लिए 11-11 पौधे मंदिर परिसर में लगाने के लिए दिए गए है। कार्यक्रम के प्रारंभ में नाड़ी वैद्य पंडित तिवारी ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले शिविर में श्वास संबंधी रोगों के मरीजों को नाड़ी परीक्षण कर निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि दी जाती है। औषधि, गाय के दूध से बनी चावल की खीर केले के पत्ते पर दी जाती है।

शिविर में हजारों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। शिविर का आयोजन अखंड आयुर्वेद भवन महौबा ने किया। श्रीराम जानकी हनुमान मंदिर के महंत श्रीराम दास, पार्षद श्रीमती उर्मिला मौर्य और श्रीमती शिरोमणी शर्मा सहित अन्य गणमान्य शामिल थे।

भोपाल में नहर खुलवाने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

- **किसान बोले-पानी नहीं मिला तो फसल चौपट हो जाएगी; क्यों बंद की, पता नहीं**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रापड़िया में नहर से जुड़े नाले को बंद करने का मामला सुर्खियों में है। पूर्व पार्षद कामता पाटीदार की जलसंसाधन विभाग की एसडीओ रव्यनीता जैन से अभद्रता के बाद अब वे किसान मैदान में उतर गए हैं, जो नहर खुलवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। गुरुवार को 20 से ज्यादा शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। किसान विवेक पाटीदार ने बताया, एसडीओ ने नहर बंद कर दी है। इसकी शिकायत जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर से की है। पानी नहीं मिलने से कई

किसानों की फसलें चौपट हो जाएंगी। कृषक हेमराज पटेल ने बताया, वे बगरोदा में रहते हैं, लेकिन उनकी जमीन रापड़िया में है। 25 साल से नहर से पानी ले रहे हैं। इसका राजस्व भी चुका रहे हैं, लेकिन अब इसे बंद कर दिया है। ऐसे में रबी फसल नहीं ले सकेंगे।

शिकायत में यह

शिकायत में लिखा है कि वर्ष 1998-99 में तत्कालीन एसडीओ कि शोर शर्मा द्वारा किसानों की सहमति से नहर बनाई गई थी। इसमें करीब 25 किसानों ने सहमति से शासन को नहर के लिए जमीन दी थी। इसका राजस्व भी बीते 2001 से दो साल पहले तक जमा करते आ रहे हैं। एसडीओ रव्यनीता जैन ने जबरिया इस नहर को बंद कराने का प्रयास किया।

सीएम हेल्पलाइन में कर रहे शिकायत

कृषक पाटीदार ने बताया कि अफसरों से शिकायत करने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ताकि, बंद नाले को फिर से खोल दिया जाए। कलेक्टर से मांग की गई है कि वे जल्द ही नाला खोल दें। ताकि, रबी फसलों की बोवनी हो सके। एसडीओ और उनकी टीम कलियासोत डैम से निकलने वाले नाले को बंद कराने पहुंची थी। बीजेपी नेता ने जेसीबी से चाबी निकाल ली थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीं महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि वाल्मीकि जी के अमूल्य विचार मानवता की सेवा, न्याय और सद्भाव के लिये समर्पित रहने की सीख देते हैं। उनके आशीर्वाद से सबका अंतस राममय हो,यही प्रार्थना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'अभिधम्म दिवस' पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'अभिधम्म दिवस' की समस्त प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि तथागत भगवान बुद्ध की कृपा की अमृत वर्षा से यह धरा पवित्र हो; मनुष्य के जीवन में अपरिमित सुख, शांति और प्रेम का वास हो तथा उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता को शुभ, शुभता व मंगलकारी प्रकाश से आलोकित करती रहें, दिव्य-पवित्र-अनुपम अभिधम्म दिवस पर यही शुभेच्छा है।

उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत, जारी होंगे नियुक्ति पत्र

स्कूल शिक्षा विभाग 8,720 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया करेगा

848 अभ्यर्थियों को 45 दिन में नियुक्ति देने का आदेश जारी

भोपाल (नप्र)। उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी में भी जुट गया है। इससे करीब प्रदेश के चार हजार पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। उच्च न्यायालय ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ईडब्ल्यूएस के पात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है। 12 नवंबर से विभाग नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर देगा। अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। आठ हजार 720 पदों पर भर्ती होनी है। यह पद स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में हैं।

ये है पूरा मामला

स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग-1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई थी। 29 सितंबर 2022 को नियुक्ति प्रक्रिया को नई भर्ती बताकर

ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई। इससे 848 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी, जबकि इस भर्ती को भी वर्ष 2018 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही की गई थी।

इस पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा दी। इस कारण नई भर्ती पर रोक लगा दी गई। उच्च न्यायालय ने 848 अभ्यर्थियों को 45 दिन में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

पदवृद्धि की भी उम्मीद

स्कूल शिक्षा विभाग अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 भर्ती के लिए पहली काउंसलिंग ही कर रहा है। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर विभाग ने विषयवार खाली पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से परामर्श भी ले लिया है।

बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत करीब 300 अभ्यर्थी परेशान

उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 पात्रता और चयन परीक्षा की नियमावली में स्कूल शिक्षा ने एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के नियमों का पालन नहीं किया। इसमें बीएड के प्रथम वर्ष में प्रवेशित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। भर्ती के समय यह उल्लेख किया गया था कि दस्तावेज सत्यापन या काउंसलिंग के समय डिग्री पूरी होनी चाहिए। पात्र अभ्यर्थी लक्ष्मण सिंह राठौर का कहना है कि अब बीएड कर चुके करीब 300 पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नियमों में संशोधन करते हुए बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को वर्ग-1 में नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है।

संपादकीय

जम्मू कश्मीर में बदलाव का दौर

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की शपथ ग्रहण के साथ राज्य में एक दौर की शुरूआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उमर को शुभकामनाएं दीं तो राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उम्मीद जताई कि नई सरकार बिना टकराव से सुगमता से अपना काम करेगी। सीएम उमर और एलजी मनोज सिन्हा के बीच आगे रिश्ते कैसे रहते हैं, यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिकारों को लेकर टकराव कभी भी और किसी भी बिंदु पर हो सकता है। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत दिए हैं कि वो सबको साथ लेकर, आपसी सौहार्द्र और क्षेत्रीय व धार्मिक संतुलन के साथ काम करेंगे। इसका पहला संकेत उन सुरिंदर चौधरी को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाना है, जो हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के विस चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ लड़ी और जीती। बावजूद इसके सात विधायकों वाली कांग्रेस ने अभी सरकार से दूरी बनाए रखी है। वह सरकार का बाहर से समर्थन करेगी। यह पार्टी का रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, जिसका मकसद राज्य में कांग्रेस के जनाधार को बचाए रखना है। कांग्रेस राज्य में धारा 370 और धारा 35 ए की वापसी के बारे में मौन है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पहले की तरह पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है। वैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा मोदी सरकार ने भी किया है, लेकिन यह कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि यदि अब्दुल्ला सरकार में भी राज्य में शांति रही, आतंकवाद काबू में रहा और अलगाववादी गतिविधियां नहीं बढ़ीं तो राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा केन्द्र सरकार दे सकती है। लेकिन यह सब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्यशील और समझ पर निर्भर करता है। क्या वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरह मुद्दे पर केन्द्र से टकराव के रास्ते पर चलेंगे या फिर यथा संभव समन्वय व संवाद के जरिए सत्ता संचालन करेंगे, यह आगे स्पष्ट होगा। फिलहाल उनका सुर समन्वय का ही ज्यादा लगता है। वैसे भी मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला के अधिकार सीमित ही हैं। राज्य की पुलिस और अन्य कई अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होंगे। उमर के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों पहले जम्मू-कश्मीर के एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन के 24 घंटों के बीच दो अहम फ़ैसले लिए। हाल में जारी किए नए जम्मू और कश्मीर पुलिस (गज़ेटेड) सेवा भर्ती नियम, 2024 के तहत कहा गया है कि पुलिस में की जाने वाली सभी सीधी भर्तियां जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग करेगा। साथ ही प्रमोशन या पदोन्नति के मामले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी (डीपीसी) तय करेगी। पूर्व में राज्य में पुलिस विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए जम्मू-कश्मीर का अपना भर्ती बोर्ड था। संशोधित नियमों के मुताबिक़ जम्मू-कश्मीर पुलिस लेफ़्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में आती है और उसके कामकाज में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होगी। इस आदेश के एक दिन बाद 11 अक्टूबर को लेफ़्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010 के तहत भर्ती नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया। इसके तहत अन्य सेवाओं में भी भर्ती का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। इनको लेकर सरकार व उपराज्यपाल में टकराव हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि नई सरकार भारत के संविधान के तहत बनी है। अब जम्मू कश्मीर के अलग विधान और निशान का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। यह कश्मीर के भारत में पूरी तरह विलय का परिचायक है और स्वागतेय है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

हिबाकुशा को नोबेल शांति के मायने

अब आज दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ सी लगी है। विश्व के नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इज़राइल और उत्तर कोरिया। कुल मिलाकर, वैश्विक परमाणु भंडार 12,000 से अधिक हथियारों के करीब है। निहॉन हिदायनको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का हिमायती रहा है। उसने समय-समय पर राज्यों से अपील की है कि हमें परमाणु रहित विश्व बनाने की आवश्यकता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संस्था निहॉन हिदायनको को देने का फैसला किया है तो इसमें भी देखा जाए तो बहुत देरी हुई है। कायदे से यह पुरस्कार बहुत पहले ही हिबाकुशा पाने का हक़दार बन गया था फिलहाल हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, के परमाणु बम से बचे लोगों के इस जमीनी स्तर के आंदोलन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के अपने प्रयासों के लिए शांति पुरस्कार मिल ही गया जिसका अपने स्थापनाकाल से ही यह नारा रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए।

निहॉन हिदायनको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की आवाज बनकर उभरा है। नोबेल शांति पुरस्कारों की लंबी रेस में एक दिन जापान की निहॉन हिदायनको यानी हिबाकुशा को यह सम्मान मिलेगा, संस्थापकों को भी इसका अंदाजा नहीं था। हिबाकुशा के लोग आज अपने काम पर गर्व कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति ब्यूरो-आईपीबी द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निहॉन हिदायनको यानी हिबाकुशा व प्रोफेसर जोसेफ रोटब्लैट को 1994 में नामांकित किया गया था। निहॉन हिदायनको के नामांकन का कारण यह उल्लिखित किया गया था कि उसने सभी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने में अथक परिश्रम जारी रखा है और न केवल परमाणु हथियारों के खिलाफ, बल्कि जापानी सरकार से हिबाकुशा के लिए उसने प्रभावी मुआवजे के लिए भी एक सतत अभियान चलाया है। निहॉन हिदायनको के महासचिव योशियो सैटो ने 10 फरवरी, 1994 में एक बयान जारी करके कहा था कि हम नामांकन का दिल से स्वागत करते हैं। बात आई गई हो गयी थी लेकिन इस साल जब इस महनीय कार्य को सम्मान मिला तो निःसंदेह हिबाकुशा को अपने किये गए अबतक के प्रयास पर संतोष हुआ होगा। इससे एक बात सिद्ध हुई कि सही प्रयास व्यर्थ नहीं जाते।

अब आज दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ सी लगी है। विश्व के नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इज़राइल और उत्तर कोरिया। कुल मिलाकर, वैश्विक परमाणु भंडार 12,000 से अधिक हथियारों के करीब है। निहॉन हिदायनको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का हिमायती रहा है। उसने समय-समय पर राज्यों से अपील की है कि हमें परमाणु रहित विश्व बनाने की आवश्यकता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संस्था निहॉन हिदायनको को देने का फैसला किया है तो इसमें भी देखा जाए तो बहुत देरी हुई है। कायदे से यह पुरस्कार बहुत पहले ही हिबाकुशा पाने का हक़दार बन गया था फिलहाल हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, के परमाणु बम से बचे लोगों के इस जमीनी स्तर के आंदोलन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के अपने प्रयासों के लिए शांति पुरस्कार मिल ही गया जिसका अपने स्थापनाकाल से ही यह नारा रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए।

हमारी धरती का द्वितीय विश्व युद्ध का समय भयभीत करने वाला काला-अध्याय है जिसने अगस्त 1945 में जापान के आसमान में दो परमाणु हमले के इतिहास दर्ज किए हैं। इनमें हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त के हमले किये गए थे। इसमें मानवीय क्षति हुई। प्राकृतिक क्षति हुई। इसमें धन-जन के साथ भविष्य का एक रोगयुक्त व भययुक्त जो समाज बचा, वे निरंतर रेडियोधर्मी किरणों की चपेट में आकर मरते रहे। दो परमाणु बमों ने हिरोशिमा और नागासाकी के अनुमानित 120,000 से 140,000 निवासियों को मार डाला था। उस त्रासदी इसके बाद के महीनों और वर्षों में जलने और विकिरण की चोटों से जो मृत्यु हुई, वह आज भी रूह कंपा देती है। इस त्रासदी की उपज है हिबाकुशा। कहते हैं हिरोशिमा और नागासाकी की आग से बचे लोगों का भाग्य लंबे समय तक छुपाया गया और उपेक्षित रखा गया। 1956 में, प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियार परीक्षण के पीड़ितों के साथ स्थानीय हिबाकुशा संघों ने जापान परिसंघ ए- और एच-बम पीड़ित संगठनों का गठन किया, तो कुछ नई बात शुरू हुई।

आज परमाणु शक्तियाँ अपने शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर रही हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि कई देश परमाणु हथियार हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। चल रहे युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। आज़ मानव इतिहास के इस क्षण में, हमें खुद को यह याद दिलाना ज़रूरी है कि परमाणु हथियार क्या हैं? दुनिया में अब तक देखे गए सबसे विनाशकारी हथियार के परिणाम क्या रहे हैं? ऐसे समय में हिबाकुशा की बुलंद आवाज़ कह रही है कि हिरोशिमा जैसे हमले अब और नहीं। नागासाकी जैसे हमले अब और नहीं। एक और नागासाकी और हिरोशिमा अब बिलकुल नहीं।

परमाणु हथियारों को, सबकी भलाई की ख़ातिर, पृथ्वी की भलाई की खातिर और जलवायु व अपनी ब्रह्मांडीय सुरक्षा की खातिर भी सचमुच यह आवाज़ उठाने का समय है। यूक्रेन, रूस और इस्राइल या नाटो से जो परमाणु धमकियां मिल रही हैं, वे बहुत हलके में नहीं ली जानी चाहिए। हाल ही मई महीने में हिबाकुशा ने साफ-साफ कहा था दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर धकेल मानवता के विनाश का खतरा मंडरा रहा है। जापान में परमाणु बम विस्फोटों ने कई लोगों की जान ले ली और हमारे शरीर, जीवन आदि पर इसका प्रभाव जारी है। परमाणु हथियारों के प्रयोग की त्रासदी, जिसका परिणाम अमानवीय निकला, कभी भी दोहराए नहीं जाने चाहिए। हिबाकुशा परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि में अरुचि और परमाणु हथियारों के भंडारण, स्थानांतरण, उपयोग की धमकी से चिंतित दिखा है। उसने साफ कहा हम, हिबाकुशा, संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों और उनके समर्थक देशों से दृढ़तापूर्वक आग्रह करते हैं कि इस लंबे समय तक चले युद्ध को समाप्त करने के लिए तुरंत संवाद शुरू करें। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता।

निहॉन हिदायनको दरअसल यह चाहता है कि 1945 में, हिरोशिमा में 140,000 से अधिक लोग मारे गए थे और इससे भी अधिक नागासाकी में 70,000 और जो लोग किसी तरह बमबारी से बच निकलने में कामयाब रहे, उन्हें जीवित रहना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति न दुबारा न आए। आज के परमाणु हथियारों में कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति है। वे लाखों लोगों की जान ले सकते हैं और जलवायु पर विनाशकारी प्रभाव डालेंगे। परमाणु युद्ध हमारी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वास्तव में दुनिया को परमाणु निरस्त्रीकरण की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाया है। अगस्त 1945 के परमाणु बम हमलों के जवाब में, एक वैश्विक आंदोलन खड़ा हुआ हिबाकुशा जिसके सदस्यों ने परमाणु हथियारों के उपयोग के विनाशकारी मानवीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, उसे नोबेल शांति पुरस्कार से प्रोत्साहित किया है। और एक तरह से विश्व को यह सन्देश दिया है कि परमाणु हथियारों के उपयोग को नैतिक रूप से अस्वीकार्य कर दिया जाय।

'परमाणु निषेध' वैश्विक स्वीकृति बने। नोबेल समिति के इस सम्मान के मायने यह भी निकल रहे हैं कि जिन्होंने शारीरिक पीड़ा और दर्दनाक यादों के बावजूद, शांति के लिए आशा और प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए अपने महंगे अनुभव का उपयोग करने का विकल्प चुना, वे सम्माननीय हैं और अब परमाणु हथियारों का उपयोग सुरक्षित पृथ्वी के लिए बिलकुल ज़रूरी नहीं है। दुनिया को परमाणु निरस्त्रीकरण की तत्काल आवश्यकता है। यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने जब यह कहा कि ये सटीक समय है कि विश्व नेतागण भी, हिबाकुशा की ही तरह, स्पष्ट नज़र रखें। परमाणु हथियारों को उनके असली रूप में ही देखें। जो मृत्यु उपकरण हैं, जो कोई सुरक्षा, संरक्षण या हिफ़ाज़त मुहैया नहीं कराते। उन तमाम परमाणु हथियारों को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र गर्व के साथ हिबाकुशा के साथ समर्थन में मुस्तैद है जो एक परमाणु मुक्त विश्व के निर्माण के लिए हमारे साझा प्रयासों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। देखा जाए तो यह बयान संसार की आज की अति अनिवार्य जीवन शर्त है। निहॉन हिदायनको-हिबाकुशा सतत काम कर रहे हैं। विश्व के देश व उनके नेतृत्व कब सोचेंगे, देखना यह है। पृथ्वी जब भी परमाणु मुक्त होगी, निश्चय ही भय की काली रात की जगह भोर का सूरज उगेगा और चहुओर एक नया वातावरण देखने को मिलेगा। जो भी हो इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं ने यह बता दिया है कि उनकी मेहनत विश्व में प्रेरणा की कुंजी हैं। नोबेल समिति ने भी यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई संकल्प मानवीय होगा और उसके सतत प्रयास जन-उद्धार व संसार के हित में होंगे तो ऐसे मिशन का सम्मान एक दिन सभी करेंगे।

राजनीति

ललित गर्ग
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जम्मू-कश्मीर में महका लोकतंत्र, सरकार से बड़ी उम्मीदें

आखिरकार जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की धूप खिल ही गयी, पांच साल बाद केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर को निर्वाचित सरकार मिल गयी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने के बाद केन्द्र शासित प्रदेश में यह पहली चुनी हुई सरकार है, जो नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। उमर अब्दुल्ला पहले भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी यह पारी हर तरह से खास है। नई सरकार के मुखिया के तौर पर उमर अब्दुल्ला के सामने आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कठिन चुनौती भी है। जनता ने विकास और शांति की आकांक्षा के साथ दिल खोलकर मतदान किया और अपनी उम्मीदों की सरकार चुनी है। घाटी में दशकों तक अब्दुल्ला परिवार के शासन के अनुभव के मद्देनजर घाटी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा जताया। तमाम ऊहापोह, सुरक्षा चुनौतियों तथा विदेशी दखल की तमाम आशंकाओं को निर्मूल करते हुए जम्मू-कश्मीर के जनमानस ने स्पष्ट सरकार बनाने का जनादेश दिया है। इस भूमिका तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द्र का वातावरण बनना ऐसे ही प्रयासों की सार्थक निष्पत्ति है। नई सरकार को विकास की चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए आतंकमुक्त कश्मीर के संकल्प को मंजिल तक पहुंचाना होगा।

जम्मू एवं कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का गठन अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेगा बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। बहरहाल, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार और केंद्र का दायित्व है कि घाटी के लोगों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की आकांक्षा जतायी है, उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। एक समय राज्य में मतदाता डर कर मतदान करने हेतु नहीं निकलते थे। मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहता था। इस बार मतदाता निर्भीकता के साथ मतदान करने निकले। जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के संकल्प को सकारात्मक समर्थन दिया है। यद्यपि लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी नहीं मिल पायी थी, लेकिन जनता ने उन्हें राज्य में सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं दूसरी ओर, इस भारी मतदान व स्पष्ट बहुमत का एक निष्कर्ष यह भी है कि लोग घाटी में शांति और सुकून, अमन एवं विकास, सौहार्द्र एवं सद्भावना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा कि इस क्षेत्र में शांति कायम होने के साथ विकास की नई बयार चले। जिसमें आम नागरिक खुद को सुरक्षित अनुभव करते हुए राष्ट्रीय विकास की धारा के साथ-साथ कदमताल कर सके।

निश्चित ही उमर के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, आम लोगों को भी उनकी कठिनाइयों का अंदाजा है, वहीं खुद उमर ने भी व्यावहारिक नजरिया अपनाने का संकेत दिया है। चुनाव के दौरान अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग पर कड़ा रुख अपनाने वाले उमर ने चुनाव नतीजे आने के बाद इस मसले पर अपना रुख नरम कर लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, जिनमें इस मुद्दे पर जोर देने का किसी को कुछ फायदा होगा। उम्मीद बढ़ाने वाली बात यह भी है कि चुनावी कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए सभी पक्षों ने सहयोग का रुख अपनाने का संकेत दिया है। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई सरकार के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है बल्कि खुद उमर ने भी उपराज्यपाल से टकराव की बजाय आपसी समझ एवं सकारात्मकता से शासन करने की मंशा जतायी है, जो जहां जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में है वही उमर की राजनीतिक सूझबूझ, परिपक्वता एवं विवेक का परिचायक है। चाहे उपमुख्यमंत्री पद जम्मू संभाग से चुने गए विधायक सुरिंदर चौधरी को स्थान देने की बात हो या कांग्रेस के लिए कैबिनेट में स्थान खाली रखने की, उमर अब्दुल्ला यह संकेत दे रहे हैं कि वह सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस ने फिलहाल सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसका कारण राज्य का दर्जा न मिलने को बताया है। उमर को हर कदम सावधानी से उठाने होंगे ताकि कोई भी स्थिति मंत्री पदों की संख्या का या इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मतभेद एवं टकराव का न बन जाए। उमर के एक-एक फैसले पर कैबिनेट और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का मसला सामने आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर की नई सरकार उमर के नेतृत्व में कितने सधे कदमों से आगे बढ़ती है। क्योंकि सरकार को अपना दायित्व इस बात को ध्यान में रखकर निभाना होगा कि केंद्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं।

केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का खासा उत्साह लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती दे रहा है। कहीं न कहीं जनता ने स्पष्ट संदेश भी दिया कि वे हिंसा, अस्थिरता, आतंकवाद व अलगाववाद से छुटकारा चाहते हैं। जाहिरा तौर पर नई सरकार के सामने व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने की चुनौती होगी। इसलिये जम्मू-कश्मीर में नई सरकार को व्यापक जनाकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए बदली हुई शासन व्यवस्था के साथ भी साम्य स्थापित करना है। इस बात का अहसास उमर अब्दुल्ला को भी है कि शासन चलाने में अब पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं होगी। विश्वास किया जाना चाहिए कि कम से कम सीमावर्ती घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए इस केंद्रशासित प्रदेश में वैसा टकराव देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच देखने को मिलता रहा है। विश्वास करें कि नई सरकार को प्रशासनिक मामलों में नौकरशाही का पर्याप्त सहयोग मिलता रहेगा।

नीति-नियंताओं को ध्यान रखना होगा कि सरकार चलाने में किसी भी तरह का अनावश्यक व्यवधान कालांतर अशांति का वाहक बनेगा। उम्मीद करें कि यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की विसंगतियां दूर की जा सकेंगी।

राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, उसमें नई उम्मीदों को पंख लगे हैं। अलगाव से बाहर निकलने का नया विश्वास जगा है। पाकिस्तानी आतंकी सोच के नुकसान को प्रांत ने झेला और महसूस किया है। गुलाम कश्मीर के लोगों की दुर्दशा को देखा जा रहा है। इसीलिये इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक सरकार बनायी है, जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान उमर की भविष्य के शासन एवं नीतियों पर टिकी है। निश्चित ही इस नई सरकार से उम्मीद जगी है कि उसके प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही नई सरकार एवं उमर के नेतृत्व की सार्थकता है।

क्रेडिट कार्ड के जाल में जेन जेड मछली

कटाक्ष

शांतिलाल जैन
लेखक व्यंग्यकार हैं।

एक मछली और मर गई
इसमें हैरत की कौनसी बात है!

बात है श्रीमान। काया इंसान की, मगर काँटे में मछली की तरह फँस गई थी। जेन ज़ेड पीढ़ी का वय। महज़ साढ़े पच्चीस बरस की उम्र। अपने कमरे में, अपने ही पंखे से, अपनी ही बेडशीट का फंदा लगाकर, अपनी ही जान ले ली। कार्पोरेट मछुआरे के बिछाए आकर्षक लुभावने जाल में फँस गई थी वो। क्रेडिट कार्ड का जाल। प्लैटिनम एलिट कार्ड। नाम से ही अमीरी टपकाता। कार्ड प्लास्टिक का, तासीर लोहे की। मेग्नेटिक स्ट्रिप उसे खेंच रही थी। बाज़ार के समंदर की लहरें उसे जाल की तरफ धकेल रही थीं तो कैसे नहीं फँसती!! 'ये क्रेडिट कार्ड हम खास आपके लिए लाए हैं।' कोमल, मधुर, मखमली आवाज़ में की गई जादुई पेशकश ठुकरा पाना मुश्किल था। वो भी मना नहीं कर सकी थी। जाल में फँस ही गई।

जेन-ज़ेड मछली जब फँसी तो दम एक-दम से तोड़ा नहीं था। छटपटाती रही, तड़पती रही, पछताती रही मगर बच नहीं सकती थी। उसकी नींद काफूर हो चुकी थी और चैन सिरे से गायब। खरीदी का पहला महीना ख़त्म हुआ, मिनिमम ड्यूज चुकाया और बचे बेलेंस के साथ दन्न से आ धंसी कर्ज के दलदल में, फिर और धंसी, थोड़ा और धंसी। दलदल शनै-शनै गहराता जाता था। पहले अठारह, फिर चौबीस, फिर छत्तीस परसेंट ब्याज की गहराई में वो उतरती-धंसती चली गई। उसके आगे हाराकिरी करने की नौबत आन पड़ी।

कार्पोरेट मछुआरे ने जेन ज़ेड मछली को जादुई कालीन से उपभोग की दुनिया की सैर कराने का रोमांचक सपना दिखाया था। वो कब कालीन पर बैठ कर उड़ चली पता ही नहीं चला। आकर्षक खूबसूरत फ्रेंड के साथ सातवें आसमां की सैर पर पहुँची। यहाँ उसे आईफोन मिला, बाईक मिली, एसयूवी बुक की, होम थियेटर मिला, महंगे डिज़ाइंड अप्पैरल्स मिले, हॉलीडे होम मिला, लक्ज़री स्टे मिला, बिग बनयान मर्लोट का ड्रिंक और लज़ीज़ इंटरकॉन्टिनेंटल खाना। पूरे महीने मौज, मस्ती, फन अनलिमिटेड। मंत्रमुग्ध थी। उसे लगा कि कारूं के खजाने की चाबी उसकी ज़ेब में आ गई है। कहाँ समंदर में पड़ी रही अब तक, असली दुनिया तो यहाँ है, उपभोग के आसमान में। और, कमाल ये कि उसे कहीं कोई भुगतान नहीं करना पड़ा। बस बेचवाल की मशीन में कार्ड से चीरा लगाया और विलासिता की भव्य दुनिया में प्रवेश कर गई। महीना पूरा होने तक यहाँ एन्जॉय के सिवाय कुछ नहीं था। जो भी है बस एक यही पल है। पूरा आसमान तुम्हारा है बस ओटीपी सही से डालना। फिर एक दिन बैंक से स्टेटमेंट मिला और जादुई कालीन एक मज़बूत जाल में बदल गया। जेन-ज़ेड मछली पूरी तरह गिरफ्त में आ चुकी थी।

क्या पूछा आपने श्रीमान कि मछली के कांटे में चारा कौनसा लगाया था? कमाल करते हैं आप। बड़े, आकर्षक, लुभावने, रंगीन, पूरे पेज के विज्ञापन नहीं देखे आपने? कॅशबैक का चारा। नो कास्ट ईएमआई का चारा। डिसकाउंट का चारा, रिवार्ड पॉइंट्स का चारा, लॉयल्टी पॉइंट्स का चारा। एयरपोर्ट के लक्ज़री लाऊंज़ में फ्री इंट्री का चारा। होलीडेईंग में छूट की चारा। कैशबैक, रिवार्ड, लॉयल्टी पॉइंट्स के बदले मालदीव्स की मुफ्त सैर का चारा। नए नए टाईप के चारे। चारे का चस्का। चस्के के काँटे में फंसी जेन ज़ेड के पास छुड़ाकर निकल पाने की गैल न थी।

क़र्ज़ का दलदल गीला तो था मगर उसमें मछली के लायक पानी न था। कुछ था तो वसूली का तकादा था, डेलिंक्वेंट लिस्ट में नाम था, खराब सिबिल स्कोर था और रिकवरी एजेंट के बाउन्सर्स का डर था। फ्रेंड अन-फ्रेंड हो चुके थे। रिश्तेदारों ने असमर्थता व्यक्त कर दी थी। माता-पिता ने जीवनभर की कमाई दे दी तब भी क़र्ज़ चुक नहीं पा रहा था। तो क्या करती जेन-ज़ेड मछली। फंदा लगाकर झूल गई।

कुछ लिखकर गई क्या? नहीं। लेकिन सुना है तूती जैसी आवाज़ में कुछ बोलकर रिकार्ड कर गई है जो बाज़ार के नक्कारखाने में सुनाई नहीं दे रहा है। सुन पा रहे हैं तो बस कार्पोरेट का अट्टहास, क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ के आंकड़े, जीडीपी में योगदान, क्रेडिट कार्ड कंपनी के विस्तार की योजनाओं के ऐलान। जाल अभी और लम्बा फिंकेगा। बाज़ार की शार्क का आसान शिकार जेन ज़ेड मछलियाँ। भूख बढ़ती जाती है और जेन ज़ेड इसके लिए तैयार भी है। तो प्रतीक्षा कीजिए, फंदे पर लटके अगले शिकार की। हाँ, हैरानी मत जताईएगा, यह न्यू नार्मल है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल
(लेखक व्यंग्यकार है)

वो चार आदमी, तांत्रिक और लाल नींबू कथा

चार आदमी एक तांत्रिक के दरबार में बैठे थे। उनकी परेशानी यह थी कि उनके आसपास की आबोहवा पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव है। अक्सर गांव में ऐसी समस्या के लिए घर के बुजुर्ग और मोहल्ले के चार लोग किसी बड़वे, भोपे या तांत्रिक के पास जाने की निःशुल्क सलाह ऐसे देते हैं, जैसे इस सलाह के आने पर कोई आयात शुल्क न देना पड़ता हो। वैसे भी भारतीय मन से आने वाली गैर और अगैर सलाह पर कोई कस्टम ड्यूटी थोड़े ही देना पड़ती है। अब ये सवाल उठ सकता है कि ये चार आदमी (लोग) कौन हैं? क्या ये आदिकाल से चार ही हुआ करते थे या ये बाद में एक दूनी दो और दो दूनी चार हुए। आर्यभट्ट होते तो उनसे यह सवाल पूछा जाता।

हो सकता है कि आगामी किन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह सवाल पूछ लिया जाए, जिस परीक्षा का परिणाम लॉकर में कैद रहने वाला हो। खैर, ये चार आदमी सलाह-मशविरा के घोल पीकर ही तो तांत्रिक के पास पहुंचे थे और वो तांत्रिक भी बहुत पहुंचे हुए थे। चेहरा एकदम रामसे बंधु की मूवी के शैतानी हीरो की मानिंद डरावना था और मुख मंडल पर कुटिल मुस्कान तैर रही थी। हाथ में जो कमंडल था, उसमें भी कपाल की दंत पंक्तियां हंसते हुए डरा रही थी। अचानक 'ओम फट्ट' की ध्वनि सुनाई दी और लगा पूरी दुनिया ही हिल रही है। ये चार लोग अब उस तांत्रिक के पास बैठे थे। उनमें से एक ने डरने का उपक्रम किया और बोलने के लिए मुख खोला ही था कि बाबा बोल पड़ा- 'बहुत परेशान लगते हो। कई सालों से डर सता रहा है।' चौथे में से दूसरे की हार्ट बीट बढ़ गई और वह इधर-उधर ऐसे देखने लगा, जैसे वह अभी धड़ाम हो जाएगा। बाबा फिर बोला- 'घबराओ मत बच्चा, हम जानते हैं तुम्हारी समस्या क्या है? तुम पहले तो बहुत प्रेम से रहते थे। एक-दूसरे के सुख-दुःख में शामिल होते थे। त्योहारों में शामिल होते थे। अब आपस में लड़ते हो। एक-दूसरे को फूटी आंख न सुहाते हो। फूलों की जगह पत्थरों ने ले ली है।' हिंसा ही हिंसा मकसद हो गया है। इतना सुनना था कि चारों लोग धार-धार रोने लगे और कुछ कहने को उत्सुक हो ही रहे थे कि तांत्रिक बाबा का स्वर फिर किसी गोले की तरह फट पड़ा और एक बार फिर 'ओम फट्ट' की आवाज आई। बाबा बोले- 'इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। तुम्हें तुम्हें तो आपस में लड़ाया जा रहा है। ताकि लोकतंत्र की सांसें चलती रहें।' 'एकता-अखंडता के नारे की पोटली बांध दी गई है।' अब सब जगह एक देश...एक ....का नारा बुलंद हो रहा है। बाबा ने पास की टोकरी में पड़ा एक हरा नींबू उठाया और उसे चारों दिशाओं में पहले तो घुमाया और कुछ देर तक बुदबुदाया और फिर बारी-बारी से नींबू उठाते रहे और शायद मंतर मारते रहे। ठीक वैसे ही जैसे चुनावी रैली में वादों को चारों दिशाओं में घुमाकर जनता के हाथ में पकड़ा दिया जाता है और उस वादे के लाल होने का इंतजार किया जाता है। जो जनता के साथ किया जाता है। बाबा ने भी वैसा ही किया और एक-एक नींबू उनकी हथेली में धर दिए और बोला- 'इसे तब तक न फेंकना जब तक ये लाल न हो जाए।' अगर ये लाल हो जाएगा तो समझो तुम्हारी हर समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। वो चारों लोग अब नींबू लेकर बाहर निकले और उसके लाल होने का इंतजार करने लगे और तांत्रिक अपनी तंत्र साधना में वापस लीन हो गया और ये चार आदमी हाथ में नींबू अब भी घुमा रहे हैं। इनको स्वप्न हुआ था कि इनके गांवों में हवा बहुत शुद्ध और प्रेम पूर्वक बह रही थी और अब हालात यह है कि इनमें से आदमी-आदमी के आमने-सामने खड़ा है, अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा है, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं और लोकतंत्र की पल्स रेट धीमी ही सही चल तो रही है।

दृष्टिकोण

अमृता कुमारी

खेलों में भी किशोरियों की समुचित भागीदारी होनी चाहिए

हमारे देश में अक्सर परिवार और समाज ने लड़कियों को पढ़ाई और घरेलू कार्यों तक सीमित रखा है. उन्हें खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जाता है. पहले की तुलना में अब लड़कियों का खेलों में भागीदारी के अवसर बढ़ने लगे हैं. कई अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने खेल में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. खेलों इंडिया के माध्यम से इस क्षेत्र में कई किशोरियों ने अपनी पहचान बनाई है. जिसकी वजह से ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों में महिला लीग की शुरुआत कर किशोरियों को खेल के मंच उपलब्ध कराये जा रहे हैं. पीटी ऊषा, सायना नेहवाल, मिताली राज, मैरी कॉम और निकहत जरीन जैसी खिलाड़ियों ने इस धारणा को मज़बूत किया है कि यदि लड़कियों को भी अवसर उपलब्ध कराये जाएं तो वह भी देश के नाम गोल्ड मैडल जीत सकती हैं।

खेल समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है. लेकिन इसमें लड़कियों की भागीदारी और उन्हें मिलने वाले अवसरों की बात करें तो यह एक जटिल विषय है. हालांकि पिछले कुछ दशकों में खेल प्रतियोगिताओं में लड़कियों के भाग लेने की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है, इसके बावजूद उनके सामने अभी भी कई बाधाएं हैं जो उन्हें इस क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल होने से रोकती है. पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज ने खेल को पुरुष-प्रधान गतिविधियों तक सीमित कर रखा है. लड़कियों को शारीरिक रूप से कमजोर मानकर उन्हें इससे दूर रखने का प्रयास किया जाता है. आज भी न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरी इलाकों के स्लम बस्तियों में रहने वाली किशोरियों को भी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रखा जाता है. उन्हें प्रोत्साहित करने की जगह उनका मनोबल तोड़ा जाता है.

ऐसी ही एक स्लम बस्ती बिहार की राजधानी पटना स्थित गर्दनीबाग इलाके में आबाद बघेरा मोहल्ला है. जहां रहने वाली अधिकतर किशोरियों को खेलने के अवसर नहीं मिलते हैं. यहां रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी शिवानी, जो गर्दनीबाग स्थित एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ती है, बताती है कि उसके स्कूल में बहुत सारी लड़कियां खेलों में भाग लेना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता है. खुद स्कूल के ही प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक लड़कियों को खेलने की अनुमति नहीं देते हैं. वह कहती है कि 'मेरी जैसी कई किशोरियां हैं जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहती हैं, लेकिन हमें अवसर नहीं दिया जाता है. हालांकि लड़कों को स्कूल ओर से खेलों में भाग लेने दिया जाता है, परंतु हम लड़कियों को इससे वंचित रखा जाता है.' इसी स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय रूपा कहती है कि खेल के मामले में लड़कों और लड़कियों के बीच बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है. लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जबकि हम लड़कियां इसमें भाग लेना चाहती हैं तो हमें यह कह कर हतोत्साहित किया जाता है कि तुम्हारे बस का यह खेल नहीं है. रूपा की बातों को आगे बढ़ाते हुए उसकी क्लासमेट सपना कहती है कि 'कौन सा ऐसा खेल है, जो हम लड़कियां खेल नहीं सकती हैं? हमें एक बार अवसर देकर तो देखें, हमारी क्षमता का उन्हें पता चल जायेगा.'

पटना हवाई अड्डे से महज 2 किमी दूर और बिहार हज भवन के ठीक पीछे स्थित इस मोहल्ला की आबादी लगभग 700 के करीब है. यहां अधिकतर अनुसूचित जाति समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि कुछ ओबीसी परिवार के भी घर हैं. यहां रहने वाले अधिकतर परिवार के पुरुष दैनिक मज़दूरी या ऑटो चलाने का काम करते हैं. यहां तक पहुंचने के लिए एक खुला नाला के ऊपर बने लकड़ी के एक कमजोर, अस्थाई और चरमराते हुए पुल से होकर गुजरना होता है. बारिश के दिनों में यह नाला उफनता हुआ स्लम बस्ती में प्रवेश कर जाता है. राजधानी में रहने के कारण यहां की किशोरियों को शिक्षा के अवसर तो मिल जाते हैं लेकिन खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें अभी भी पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाई गई कई बाधाओं का सामना करना होता है. इनमें सबसे बड़ी बाधा लड़कियों के प्रति समाज की नकारात्मक और पारंपरिक सोच है. इस संबंध में बस्ती की रहने वाली 17 वर्षीय काजल कहती है कि केवल स्कूल ही नहीं, बल्कि घर से भी खेल गतिविधियों में भाग लेने से रोका जाता है. यदि हम चाहते भी हैं तो यह कह कर मना कर दिया जाता है कि यदि खेल में किसी प्रकार की चोट लग गई तो भविष्य में शादी में बाधा आएगी. माता-पिता उत्साह बढ़ाने की जगह खेल गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहते हैं.

यहां रहने वाली दसवीं की छात्रा प्रीति कहती है कि 'मैं स्कूल में कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हूं. स्कूल के अंदर होने वाली खेल प्रतियोगिता में भाग लेती रही हूं. लेकिन जब भी स्कूल से बाहर जाकर या जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की बात आई, मुझे हर बार घर से इसकी इजाज़त नहीं मिली. पिता ने यह कह कर मना कर दिया कि इसमें चोट लगने की संभावना रहती है. यदि तुम चोटिल हो गई या कुछ अन्य शारीरिक नुकसान हुआ तो शादी में अड़चन आएगी. जबकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम रहती है. मैंने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन हर बार यह कहकर मुझे मना कर दिया गया कि खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना लड़कों का काम होता है. लड़कियां घर का कामकाज सीखें यही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जबकि यह सोच पूरी तरह से गलत है. कुश्ती हो या फुटबॉल, क्रिकेट हो या हॉकी, कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें लड़कियों ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े न हो. यदि हमें भी अवसर मिले तो हम भी अपने राज्य और जिला का नाम रौशन करने की क्षमता रखते हैं.'

हमारे देश में अक्सर परिवार और समाज ने लड़कियों को पढ़ाई और घरेलू कार्यों तक सीमित रखा है. उन्हें खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं किया जाता है. पहले की तुलना में अब लड़कियों का खेलों में भागीदारी के अवसर बढ़ने लगे हैं. कई अंतरराष्ट्रीय खेल संगठनों और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने खेल में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. खेलों इंडिया के माध्यम से इस क्षेत्र में कई किशोरियों ने अपनी पहचान बनाई है. जिसकी वजह से ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों में महिला लीग की शुरुआत कर किशोरियों को खेल के मंच उपलब्ध कराये जा रहे हैं. पीटी ऊषा, सायना नेहवाल, मिताली राज, मैरी कॉम और निकहत ज़रीन जैसी खिलाड़ियों ने इस धारणा को मज़बूत किया है कि यदि लड़कियों को भी अवसर उपलब्ध कराये जाएं तो वह भी देश के नाम गोल्ड मैडल जीत सकती हैं.

भारत में जैसे-जैसे महिला खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता पाई है, वैसा ही इसे लेकर लोगों का नजरिया भी बदलने लगा है. अब कई परिवार अपनी बेटियों को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. लेकिन यह अभी भी काफी हद तक शहरी क्षेत्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों तक ही सीमित है. आज भी ग्रामीण और बघेरा मोहल्ला जैसी शहरी स्लम बस्तियों की किशोरियों को खेलों में भाग लेने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है. जहां संसाधनों के अभाव के साथ साथ सामाजिक दबाव और परंपरागत सोच भी एक बड़ी बाधा है. इसके अतिरिक्त खेलों में लैंगिक असमानता बहुत बड़ी चुनौती है. जिसे समाप्त करके ही किशोरियों के लिए खेलों में अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं. इस बात में कोई दो राय नहीं कि खेलों में लड़कियों को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. यह लड़कों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है. समानता और समर्थन के बिना खेलों में किशोरियों की भागीदारी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकती है. इसके लिए सरकार और खेल संगठनों के साथ साथ समाज को भी आगे बढ़कर उनके लिए समुचित अवसर और वातावरण उपलब्ध कराने होंगे. (चरखा फीचर्स)

विडंबना

प्रदीप मिश्र

आरटीआई- बताने की नहीं, भुलाने की कोशिश ज्यादा

किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने का मंतव्य इससे स्पष्ट होता है कि इसके लिए नीति, नियम और अधिनियम क्या बनाए जाते हैं और उनका क्रियान्वयन व निगरानी कैसे की जाती है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) के हालात बताते हैं कि कड़ी मशक्कत से तैयार जनहित के कानून को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। 18 वर्ष पहले जनसामान्य को मिले इस अभूतपूर्व मौलिक अधिकार की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर यद्यपि कोई सवाल नहीं है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर गरिमा के लिए प्रयास और जागरुकता की पहल का अभाव है। अधिनियम में किए गए संशोधनों और सतर्क समूहों के सुझावों की अनदेखी भी इस बारे में चिंताएं बढ़ाती है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के डेढ़ वर्ष बाद भी आरटीआई पोर्टल शुरू नहीं किया है। इनसे 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। यहां यह जानना जरूरी है कि शीर्ष अदालत आरटीआई आवेदनों के लिए पोर्टल बना चुकी है।

आरटीआई कानून केंद्र-राज्य सरकार को ही नहीं, इनके सभी उपक्रमों को नियमों का पालन करने के साथ नियमानुसार काम करने की नसीहत देता है। अन्य कानून जहां आम जनता के लिए बनाए जाते हैं वहीं यह कानून संसद और विधानसभाओं द्वारा मान्य संस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। माना जाता है कि गोपनीयता से अनिश्चितता को बढ़ावा मिलता है और अनिश्चितता व्यवस्था को कमजोर बनाती है। सूचना अधिकार के कानून को लागू करने में सरकारों की अरुचि रही है। यह हाल तब है, जब दुनिया में सबसे ज़्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल भारत में होता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल लगभग 60 लाख आरटीआई डाली जाती हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि 2005-06 में उसके यहां आरटीआई आवेदनों की संख्या 24,436 थी। 2021-22 तक यह आंकड़ा 18,32,133 तक पहुंच गया।

भारतीय संविधान की धारा 19 (1) (क) और धारा 21 में नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों को जानने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। यह परिकल्पना 2005 में कांग्रेस के डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में साकार हुई। पारदर्शिता के परिदृश्य में बने कानून को भ्रष्टाचर से लड़ाई का सशक्त हथियार माना गया पर सरकारी पेंचीदगियों ने इसकी पहुंच आसान नहीं रहने देने के प्रयत्न किए। यही कारण है कि सूचनाओं की शुचिता बनाए रखने के बजाय संशोधन की आड़ लेकर संकोच को सार्वजनिक किया गया। संवेदनशीलता के नाम पर सूचनाएं छिपाने का पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। जन सूचना अधिकारी जानकारी देने में अनावश्यक विलंब के साथ बचने का रास्ता निकालते हैं। कई बार निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर सूचनाएं या तो दी नहीं जा रही हैं या फिर आधी-अधूरी देकर आवेदक को उलझाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोग ने 11 जुलाई 2024 से द्वितीय अपील और शिकायतों को ऑफलाइन लेने की व्यवस्था बंद कर दी है। अब ऑनलाइन द्वितीय अपील और शिकायतें ही स्वीकार की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव इसे बिडंबना बताते हुए कहते हैं कि सरकारी कार्यालयों में दोनों ही व्यवस्थाएं लागू हैं।

मध्य प्रदेश के रीवा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट संजय सिंह 2012 से अब तक एक हजार से अधिक आरटीआई लगा चुके हैं। क्या भारत आजाद है? क्या हमारा बहुत सारा टैक्स का पैसा ब्रिटेन को जाता था? रेलवे में लंबाई और वजन के आधार पर सीट के लिए क्या नियम हैं? आदि का संतोषजनक जवाब उन्हें अब तक नहीं मिल सका है। केंद्र सरकार द्वारा कामचलाऊ जवाब देकर भी वास्तविक तथ्य बताने से बचा जाता है। छत्तीसगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले आयकर भुगतान की राशि की जानकारी मांगी गई तो बीते वर्ष का ब्योरा देकर बताया गया कि भुगतान की गई राशि का विवरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह व्यक्तिगत है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। शुक्ल की तमाम आरटीआई के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के बारे में जानकारी नहीं दी है। फंड में मिली राशि और उसके खर्च के बारे में फंड की वेबसाइट भी चुप है।

भारतीय गणतंत्र के इस महत्वपूर्ण कानून पर जागरुकता का अभाव और अनदेखी इससे स्पष्ट होती है कि 12 अक्तूबर गुजर जाता है और पता नहीं चलता कि जनता को एक मौलिक अधिकार इसी तारीख में मिला था। तंत्र की इसमें दिलचस्पी नहीं है कि इस तारीख को हिंदी दिवस, शिक्षक दिवस, साक्षरता दिवस, योग दिवस और मजदूर दिवस की तरह सूचना या जानकारी दिवस का स्वरूप दिया जाए। दिन और दिनांक विशेष पर दलीय सीमाओं और निष्ठाओं से अलग हटकर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को अपनी उपलब्धियां ही बतानी चाहिए। सूचना मंत्री भी इस दिशा में किए जा रहे उपायों, बाधाओं और निष्कर्षों से परिचित कराएं। तथ्यों को लेकर संजीदगी बरतने के बहाने सूचनाओं का प्रवाह रोकने के लिए प्रयासरत समूचा तंत्र सूचनाओं की स्वतंत्रता को लेकर सामंतशाही की मानसिकता में है। केंद्र सरकार विहिसल ब्लोअर संरक्षण एक्ट लागू नहीं कर रही है। उदासीनता का परिणाम है कि सूचनाएं और दस्तावेज लेने में कई आरटीआई एक्टिविस्ट जान गंवा चुके हैं। धमकियां, रिपोर्ट, हमले और प्रलोभन आम बात हो गई है।

दूसरी ओर सतर्क नागरिक संगठन (एसएनएस) की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना और गोवा के सूचना आयोग में फिलहाल एक भी आयुक्त नहीं है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और ओडिशा में मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली हैं। नतीजा, देश के सभी 29 सूचना आयोगों में 30 जून 2024 तक 4,05,509 शिकायतें और अपीलें लंबित थीं। 31 मार्च 2019 तक 26 सूचना आयोगों में 2,18,347 मामले थे, जो 30 जून 2021 तक 2,86,325 और 30 जून 2023 तक 3,88,886 हो गए। 1,08,641 मामलों के साथ महाराष्ट्र इसमें अव्वल है।

कर्नाटक दूसरे स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 24,035 है। पंजाब में यह संख्या 9,175 है तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 4,191 और 716 है।

झारखंड में संख्या 7,728 है। यही नहीं, केंद्रीय सूचना आयोग में 30 जून 2024 तक 22,774 अपीलों-शिकायतों पर सुनवाई-फैसलों का इंतजार था। कारण, करीब एक साल से केंद्रीय सूचना आयोग में भी केवल तीन आयुक्त हैं। हालांकि रिक्तियों की बड़ी संख्या के बावजूद एक जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के बीच 28 आयोगों ने 2,25,929 मामलों का निपटारा किया है।

पहल

अशीष कोठारी

लेखक 'कल्पवृक्ष' व 'विकल्प संगम' के साथ कार्यरत हैं।
बाबा मायाराम द्वारा अनुवादित

वैकल्पिक विकास के लिए एक दशक का 'विकल्प संगम'

एक दशक पहले, भाषाविद् और विद्वान-कार्यकर्ता गणेश देवी से चर्चा में भारत में विकल्पों के संगम का विचार आया था। बाद में हम इसे लेकर ऐसे कई संगठनों और व्यक्तियों से मिले जो प्रकृति के विनाश और समुदायों के विस्थापन सहित 'विकास' की हिंसा पर सवाल उठा रहे थे और न्याय तथा पारिस्थितिकीय ज्ञान के साथ मानवीय जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा दे रहे थे। इस विचार को भारी सहमति मिलने के बाद 2014 में 'विकल्प संगम' की शुरूआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य आंदोलनों और संगठनों को एक साथ लाना था।

अलग-अलग मुद्दों पर काम कर रहे विविध सामाजिक आंदोलनों को एक साथ लाने, उनके बीच के संबंधों को समझने और बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? वैश्विक राजनीतिक, पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक संकटों से हम सामूहिक रूप से कैसे निपट सकते हैं? पृथ्वी को बर्बाद किए बिना मानवीय जरूरतों व आकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? बेहतर भविष्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है? और हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि 'कार्बन ट्रेडिंग,' 'हरित अर्थव्यवस्था' जैसे 'समाधान' जिस सत्ताधारी प्रणाली ने सुझाए हैं, वे कितने कारगर हैं? यहां तक कि 'टिकाऊ विकास' जैसी सतही पहल भी विकास-आधारित, पूंजीवादी या राज्यवादी दृष्टिकोण की मूल बातों को चुनौती नहीं देती। ऐसे सवालों का सामना करने का प्रयास 'विकल्प संगम' प्रक्रिया के मूल में है।

'विकल्प संगम' प्रक्रिया ने पांच प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया है- दस्तावेज़ीकरण, जन-सूचना, आपसी सहयोग व सहकारिता, सामूहिक दृष्टिकोण और पैरवी। कई वैकल्पिक प्रयोगों का दस्तावेजीकरण करना, उन्हें समझना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। 'विकल्प संगम' के इस भाग में पत्रकारों और शोधकर्ता-लेखकों से विकल्प की कहानियों को लिखवाना और फिल्में बनवाना शामिल है। मसलन - वर्ष 2020-22 में, जब कोविड महामारी के दौरान सामुदायिक प्रयोगों की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया गया था, 70 कहानियां 'साधारण लोगों के असाधारण कार्य' नामक श्रृंखला की पुस्तिका में प्रकाशित की गई थीं।

दस्तावेज़ीकरण के अलावा ऐसी कहानियों और केस-स्टडी को विविध पाठकों-दर्शकों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो, संगम के काम का दूसरा क्षेत्र जनसाधारण तक पहुंचना है। इसके लिए एक प्रमुख मंच 'विकल्प संगम वेबसाइट' है, जिसमें लगभग 2000 कहानियां, संदर्भ सामग्री और 100 से अधिक फिल्में तैयार की गई हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर अंग्रेजी तथा कुछ हद तक हिन्दी का प्रभुत्व बना हुआ है; लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं में इसे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

'विकल्प संगम' द्वारा विकल्प की कहानियों की एक पोस्टर प्रदर्शनी बनाई गई है, जिसे स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में दिखाया जाता है। इसके साथ ही कई पुस्तिकाएं और ग्राफिक उपन्यास का स्टॉल भी लगाया जाता है। पिछले 2-3 वर्षों में, 'विकल्प संगम' की कहानियां, सामग्री और कार्यक्रमों को विभिन्न 'सोशल मीडिया' माध्यमों से भी प्रचारित किया गया है, पर मुख्यधारा के मीडिया तक 'विकल्प संगम' की पहुंच सीमित ही रही है।

'विकल्प संगम' का तीसरा प्रमुख क्षेत्र आपसी सहयोग और एक-दूसरे से सीखना है। सबसे रोमांचक हैं, ऐसे 'विकल्प संगम' जिनमें 3-4 दिनों का जमावड़ा होता है। साल 2024 की शुरुआत तक, लगभग 30 ऐसे 'विकल्प संगम' आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें भारत के कई राज्यों/क्षेत्रों के क्षेत्रीय-संगम शामिल हैं; और ऊर्जा, भोजन, युवा, लोकतंत्र, पारंपरिक वैश्विक दृष्टिकोण, वैकल्पिक अर्थव्यवस्थाएं, स्वास्थ्य, समृद्धि और न्याय, पारंपरिक शासन और शांति पर संगम शामिल हैं। इन जमावडों में गंभीर चर्चाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय यात्राएं, शारीरिक गतिविधियां और वैकल्पिक उत्पादों का प्रदर्शन भी होता है। 'विकल्प संगम' का एक पहलू अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना और अनुभवों को आपस में साझा करना भी है, जिससे अलग-अलग खांचों को तोड़ा जा सके। इस प्रयास में कई समूह शामिल रहे हैं। 2023 में आदिवासी व अन्य सामुदायिक दृष्टिकोणों पर आयोजित 'विकल्प संगम' में आदिवासियों, खानाबदोश-चरवाहों और गैर-आदिवासी कृषक समुदायों के बीच बातचीत हुई। एक अन्य संगम में विकलांग व्यक्तियों और दूसरे में 'एलजीबीटीक्यूआईए' समुदायों के कार्यकर्ताओं ने तथाकथित 'सामान्य' लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताया।

पश्चिमी हिमालय के संगमों ने एक-दूसरे से सीखने के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों को शुरु किया जो क्षेत्र के समूहों द्वारा स्वतंत्र रूप से तीन साल से सतत जारी है। साल 2017 में आयोजित 'युवा विकल्प संगम' में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और संस्कृतियों के युवाओं को एक साथ लाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ताकि वे जिस तरह का समाज चाहते हैं और जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसे व्यक्त कर सकें। 'विकल्प संगम' का चौथा क्षेत्र सामूहिक दृष्टिकोण का निर्माण है। यह कई वर्षों से भारतीय समाज के कई वर्गों की दूरदर्शी आवाज़ों को एक साझा एजेंडा में लाने का प्रयास है। इसमें किसानों, चरवाहों, मछुआरों, औद्योगिक श्रमिकों और शिल्पकारों की आवाजें और दृष्टिकोण शामिल हैं। इन लोगों को अक्सर 'कामकाजी' माना जाता है, जबकि शहरी बुद्धिजीवी 'विचारक' माने जाते हैं। इसका सम्बन्ध लिंगभेद और जातिवाद में भी निहित है। इस झूठे द्वंद्व को तोड़ना 'विकल्प संगम' प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। 'विकल्प संगम' का पांचवां और अंतिम क्षेत्र मुद्दों की पैरवी करना है। 'विकल्प संगम' के सदस्यों को अहसास है कि राजनीतिक आलोचनाओं के बिना राजनीतिक और आर्थिक ताकतों को चुनौती देना असंभव है। कई संगमों की घोषणाओं में नीतिगत सिफ़ारिशें शामिल की गई हैं। उदाहरण के लिए 2016 में 'राष्ट्रीय खाद्य संगम' में प्रतिभागियों ने समुदाय-आधारित टिकाऊ-कृषि के पक्ष में और 'जीएम' सरसों का विरोध करते हुए एक घोषणा जारी की थी।

पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए स्थानीय संघर्षों के समर्थन में कई बयान जारी किए गए हैं, जिनमें कश्मीर और लद्दाख की स्थिति में संवैधानिक परिवर्तन, लक्षद्वीप में जीवन को सांप्रदायिक बनाने के प्रयास, ऑरोविले में सरकारी हस्तक्षेप, मणिपुर में जातीय दरारें और उन समुदायों से सीखे गए सबक जो कोविड के दौरान बरकरार रहे - इन सबमें सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई के कदम शामिल हैं।

पैरवी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास 2019 और 2024 में जारी किया गया 'न्यायपूर्ण, समतापूर्ण, टिकाऊ भारत के लिए जन-घोषणापत्र' रहा है। इनमें भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकीय मुद्दों पर विस्तृत सिफारिशें शामिल हैं। इसका उद्देश्य न केवल राजनीतिक दलों से अपने चुनाव अभियानों में इन पर विचार करने का आग्रह करना है, बल्कि स्थानीय से लेकर राज्य सरकारों तक के साथ पैरवी में उपयोग करना भी है।

दिलचस्प है कि 'विकल्प संगम' में पारंपरिक वैचारिक सीमाएं कमजोर होती दिख रही हैं। निष्ठावान गांधीवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी, दलित, आदिवासी, प्रकृति अधिकार और अन्य दृष्टिकोण वाले प्रतिभागी, जो अक्सर एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में रहते आए हैं, रचनात्मक बातचीत में शामिल रहे हैं। बैठकों का माहौल इन मतभेदों को दूर करने, या उन्हें स्पष्ट रूप से स्वीकार करने और समानताओं को लेकर आगे बढने का है। ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि 'विकल्प संगम' में आने वाले प्रतिभागी विविधता के प्रति सम्मान रखते हैं।

'विकल्प संगम' संगठन की बजाए एक नेटवर्क या मंच है। इसकी अपेक्षाकृत अनौपचारिक संरचना में एक राष्ट्रीय महासभा है जिसमें 2024 तक 90 से अधिक आंदोलन और संगठन शामिल रहे हैं। पहले कुछ वर्षों तक इसका केंद्र 'कल्पवृक्ष' संस्था थी, लेकिन 2021 से समन्वय और अगुआई लगभग 10 सदस्य-संगठनों की एक टीम में विकेंद्रीकृत हो गई है। प्रत्येक संगम का आयोजन एक या अधिक मेजबानों द्वारा किया जाता है, जिनमें आमतौर पर महासभा के सदस्य भी शामिल होते हैं।

'विकल्प संगम' 'सामान्य' लोगों की समाधान खोजने की क्षमता का महोत्सव है। इससे यह भी पता चलता है कि बेहतर समाज की परिकल्पना औपचारिक 'विशेषज्ञों' का विशेषाधिकार नहीं है। यह कहीं भी लोगों के ज्ञान और अनुभव को एक साथ रखकर किया जा सकता है। यह जीवन के विभिन्न चरणों में, विविध संस्कृतियों और आजीविका में, सीखने और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, प्रकृति या खेतों, कक्षाओं में संभव है। पिछले कुछ दशकों में हमने सीखा है कि इस प्रक्रिया को जितना अधिक लोकतांत्रिक, सहभागी, विविध और रोमांचक बनाएंगे तो कुछ लक्ष्य पूरे होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भले ही हमारी कुछ गतिविधियां राज्य की नीति को प्रभावित करने की कोशिश पर केंद्रित हों, अंततः यह लोगों का सशक्तीकरण ही है, जो परिवर्तन को आगे बढ़ाएगा। (सप्रेस)

रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

बैतूल। भाजपा नेता रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया है। बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने आरोपियों को पकड़ने वालों को तीन-तीन हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने जारी किए प्रेस नोट में बताया कि सारणी थाना के अप.क. 444 / 2024 धारा 108, 3 (5) बीएनएस अंतर्गत रविंद्र देशमुख निवासी बगडोना द्वारा स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या करने के प्रकरण में सुसाइड नोट के आधार पर 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं 8 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने के लिए इनाम की उद्घोषणा जारी की गई है। जिसके अनुसार प्रकरण के फरार आरोपी रंजीत सिंह, प्रकाश शिवहरे, भोलासिंह उर्फ रामनारायण सिंह, अभिषेक साहू, मोहम्मद नसीम रजा, शमीम हुसैन, नाजिया बानो और करण सूर्यवंशी के बारे में जो कोई व्यक्ति सूचना देगा अथवा गिरफ्तार करवायेगा, उसे पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80 (अ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रत्येक फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर तीन-तीन हजार रुपये इनामी राशि प्रदान करने की उद्घोषणा जारी की गई है। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल का मान्य होगा।

अब तक दो आरोपियों की ही गिरफ्तारी- भाजपा नेता रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में पुलिस ने अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन झारिया के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए एवं जिले की विभिन्न टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया है। अन्य राज्यों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अनुसंधान दल

(एसआईटी) का भी गठन किया गया। गौरतलब रहे कि प्रकरण के आरोपीगण घटना दिनांक से ही फरार चल रहे है।

चल-अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही प्रारंभ- घटना के बाद से ही पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। आम जनता से अपील की जाती है कि उक्त शेष आरोपियों की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल बैतूल पुलिस को सूचित कर गिरफ्तारी में सहयोग करें। इसके अतिरिक्त जो आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी चल अचल संपत्ति को विधिवत जप्त किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार प्रारंभ की गई है। राजस्व विभाग से सभी आरोपियों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है।

रविन्द्र देशमुख आत्महत्या मामले में फरार 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

संपत्तियों और बैंक लेन-देन की जांच जारी

बैतूल। थाना सारणी के अपराध क्रमांक 444/2024, धारा 108 और 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज आत्महत्या मामले में 10 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इनमें से फरार चल रहे 8 इनामी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक आज 17-10-2024 को खारिज कर दी गई है। अग्रिम जमानत निरस्त होने वाले आरोपियों में 1. रंजीतसिंह पिता सुशीलसिंह, निवासी बगडोना, 2. प्रकाश पिता केवल शिवहरे, 3. भोला सिंह उर्फ रामनारायण सिंह पिता रामलखन सिंह (तीनों निवासी शोभापुर) 4. अभिषेक पिता नरेश साहू 5. मोहम्मद नसीम रजा पिता राहत हुसैन 6. शमीम पिता राहत हुसैन 7. नाजियाबानो पति नसीम रजा 8. करण सूर्यवंशी पिता धनराज सूर्यवंशी (सभी निवासी पाथाखेड़ा, सारणी, जिला बैतूल)।

संपत्ति और आय स्रोतों की विस्तृत जाँच

फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का संपूर्ण ब्यौरा राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा रहा है। इन संपत्तियों के आय स्रोतों और वैधता की जांच के लिए गठित एसआईटी द्वारा आज सारनी क्षेत्र में गहन पड़ताल की जा गई है जो लगातार जारी रहेगी।

बैंक खाते और लेन-देन की बारीकी से जांच

फरार आरोपियों के बैंक खातों के प्रत्येक लेन-देन की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। संदेहास्पद ट्रांजैक्शन के मामले में अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। फरार इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। उनकी धरपकड़ के लिए राज्य में तथा अंतर्राज्यीय स्थलों पर लगातार छापेमार कार्यवाही जारी है तथा अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का सामना कराया जा सके।

पुलिस ने कार से बरामद की डेढ़ लाख की शराब, चालक फरार

बैतूलबाजार पुलिस ने एक कार से करीब डेढ़ लाख की शराब जब्त की है। यह कार महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है। कार का चालक बाइक सवार को टक्कर मारकर भाग निकला। जिसके बाद जब कार की जांच की गई तो उसमें शराब बरामद हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैतूल बाजार पुलिस को मोबाइल के जरिए जानकारी मिली थी कि एक अर्टिगा कार क्रमांक एमएच 01, डीपी 2696 में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। जिसके बाद सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट लगाया। जब इस कार का पीछा किया गया तो कृषि विज्ञान केंद्र के पास कार चालक ने बाइक को टक्कर

मार दी और कार को मौके पर ही छोड़ कर फरार हो गया। घटना में कार के सामने का हिस्सा और टायर वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। वाहन को क्रेन की सहायता से थाने में खड़ा किया गया। वाहन की तलाशी में अलग-अलग ब्रांड की 11 नग शराब के कार्टन और तीन नीले रंग की थैलियों में शराब पाई गई। कुल 114 लीटर अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1,63,710 है, वाहन में पाई गई। पुलिस ने कार से शराब जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना धुर्वे, उपनिरीक्षक उत्तम मस्तकार, सहायक उपनिरीक्षक रमन कुमार धुर्वे, प्रधान आरक्षक अशोक झरबड़े, आरक्षक अरुण, कमल चौरे, कमलनाथ पवार, महिला आरक्षक स्नेहल परते, और चालक प्रधान आरक्षक राजेश की सराहनीय भूमिका रही।

चाकूबाजी के विरोध में वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन

बैतूल। खंजनपुर इलाके में आपराधिक वारदातों से दहशत बढ़ रही है। इससे परेशान वार्डवासियों ने गुरुवार को प्रदर्शन कर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और इलाके में पुलिस चौकी खोलने की मांग की। उन्होंने इसका ज्ञापन भी सौंपा। वार्डवासियों ने खंजनपुर मुख्य मार्ग पर करीब आधा घंटा प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी शालिनी परस्ते और टीआई कोतवाली देवकरण डेहरिया मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों को समझाइश दी। लोगों का कहना है कि वार्ड से लगा मैदानी क्षेत्र है। जहां लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। असामाजिक तत्व शराब, गांजा और कई प्रकार का नशा करते हैं। गाली गलौज, छेड़छाड़, लूट और मारपीट करते हैं। जिससे वार्ड में भय का माहौल बना हुआ है। एएसपी ने वार्ड वासियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिसके बाद वार्डवासी मान गये। गौरतलब रहे कि मंगलवार की रात तीन आदतन अपराधियों ने खंजनपुर इलाके में बाइक पर हाथ में चाकू लहराते हुए निकले और सडक़ पर जो मिला उन्हें चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। इस घटना में 6 लोग घायल हुए, जिनमें एक गंभीर घायल को भोपाल रेफर किया गया है। इस घटना से इलाके में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। आज आक्रोशित वार्डवासियों ने सडक़ जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है।

करुणा बुद्ध विहार में वर्षावास का किया समापन

बैतूल। सुजाता महिला मंडल द्वारा करुणा बुद्ध विहार आमला में गुरुवार को 28 बुद्ध पूजा एवं वर्षावास का समापन किया गया। वर्षावास के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गडरे द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान उपासकों द्वारा फलों और सब्जियों की आकर्षक आकृति बनाई गई। भंते गिरिमानंद द्वारा बताया गया कि एक समय बाद हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा और बस अच्छे कर्म और आचरण रह जायेगें। उन्होंने तथागत बुद्ध पर कहा कि विश्व शांति के लिए हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उपासक एवं उपासिकाओं को परित्राण जल वितरण के साथ ही परित्राण सुत्त बांधा गया। सुजाता महिला मंडल ने बताया कि आषाढ़ की पूर्णिमा से वर्षवास प्रारंभ हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध की साथ-साथ सभी 28 बुद्ध की पूजा विधि विधान पूर्वक की गई। इस अवसर पर उपासिका कांता हरमाड़े, वत्सला अतुलकर , निर्मला पंडोले शीला सूर्यवंशी, ऋतु डोंगरे सहित अन्य उपासक-उपासिकाएं उपस्थित रही।

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर किया पौधारोपण

बैतूल। संस्कृत भाषा के आदि कवि और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती गुरुवार को ग्रीन आर्मी युवा मंडल द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर ग्रीन आर्मी युवा मंडल ने जामठी में पर्यावरण संरक्षण के तहत औषधिय एवं फलदार पौधों का रोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। ग्रीन आर्मी युवा मंडल के प्रमुख ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, जो हमें प्रभु श्री राम के सत्यनिष्ठ पिता प्रेम और उनका कर्तव्य पालन और अपने माता तथा भाई-बंधुओं के प्रति प्रेम-वात्सल्य से रूबरू करवाकर सत्य और न्याय धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे महान समाज सुधारक रहे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के जीवन से संबंधित जानकारी दी और युवाओं को रामायण के आदर्शों पर चलने के लिये प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का संकल्प लिया।

अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, मौत

बैतूल। अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्ट मार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक योगेश अतुलकर (33) पुताई का काम करता था। बुधवार रात वह घर से निकलकर पड़ोस में स्थापित की जा रही लक्ष्मी जी की प्रतिमा पंडाल में जा रहा था, इसी दौरान सारणी स्टेट हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के सिर, नाक, पेट और सीने पर गंभीर चोट लगी है। किसी व्यक्ति ने डायल हैंड्रेड को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर परिजनों को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक का शव जिला अस्पताल लाया गया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

पुलिस ने पकड़ी रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, मामला दर्ज

बैतूल। अवैध रेत का परिवहन करते पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि मरामझिरी के पास एक व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्रॉली में चोरी की रेत भरकर ले जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम रवाना हुई, जहां मरामझिरी मजार के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी, जिसे रोककर जांच की गई। ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम महेश सलाम पिता गोकुल उर्फ राधे सलाम, निवासी आमढाना थाना रानीपुर बताया। उसने बताया कि रेत मरामझिरी के नाले से भरी गई है। जब ट्रैक्टर चालक से रेत से संबंधित रॉयल्टी के बारे में पूछा, तो चालक कोई रॉयल्टी नहीं दिखा सकी। जिसके बाद पुलिस ने बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर धारा 379 (2) बीएनएस एवं 03 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत आरोपी महेश सलाम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। वास्तविक वाहन स्वामी की भूमिका की जांच के उपरांत उसे भी आरोपी बनाया जाएगा।

पुलिस ग्राउंड में बन रहे ट्रैकिंग की चौड़ाई 12 फुट होगी

बैतूल। बैतूल के पुलिस परेड ग्राउंड में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे वाकिंग ट्रैकिंग का काम अब शुरू हो गया है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने पर वाकिंग जॉगिंग करने वालों ने गुरुवार को सुबह ग्राउंड पहुंचे विधायक हेमंत खंडेलवाल से इसकी चौड़ाई बढ़ाने की मांग की। विधायक श्री खंडेलवाल ने तुरंत मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारी को ट्रैकिंग की चौड़ाई 12 फुट करने का निर्देश दिया है । जानकारी के मुताबिक इन दिनों बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल बैतूल शहर के विकास और अन्य कार्यों में गुणवत्ता और सुंदरता को ध्यान में रखते हुए स्वयं पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं । इसी क्रम में आज बैतूल के पुलिस ग्राउंड में 55 लाख की लागत से एक किलोमीटर लंबी बन रहे वाकिंग ट्रैकिंग को देखने पहुंचे। इस दौरान वॉकिंग जॉगिंग करने वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने ट्रैकिंग की चौड़ाई को बढ़ाने की मांग की। साथ ही पानी निकासी के लिए भी व्यवस्था बनाने की बात कही। इन सब बातों को श्री खंडेलवाल ने ध्यान से सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ट्रैकिंग की चौड़ाई 12 फिट करें, साथ ही पानी के निकासी की व्यवस्था बनाए। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि दो-तीन दिन में बैतूल के नए सीएमओ आ जाएंगे। इसके बाद पुनः इस विषय पर मौके पर पहुंचकर चर्चा की जाएगी तथा आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में प्रतिदिन वॉकिंग जॉगिंग करने वालों में वार्ड पार्षद नितेश पिंटू परिहार सहित सेवानिवृत्ति बैंक ऑफिसर बलराम जसूजा, हरीश गढ़ेकर, वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार संजय द्विवेदी, वरिष्ठ एडवोकेट संजय मोखड़े एवं अजय दुबे, समाजसेवी हेमंत बत्रा, आलोक तिवारी, सुरेश गायकवाड़ आदि ने ट्रैकिंग की गुणवत्ता पर ध्यान रखने की बात भी इस दौरान कही।

कचरा वाहन कर्मचारी हड़ताल पर, चरमराई सफाई व्यवस्था

बैतूल। कचरा गाडियों के अस्थाई कर्मचारियों ने ठेका कंपनी ओम सांई विजन पर ईपीएफ न देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि जब भी वो ईपीएफ का मुद्दा उठाते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हें काम से निकालने की धमकी देता है। उनकी मांग सिर्फ ईपीएफ और अनुभव प्रमाणपत्र की है। जिस पर कंपनी हमें धमकाकर चुप करवाना चाहती है। जिसके विरोध में अस्थाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गये। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। हड़ताल की वजह से शहर में जगह-जगह कचरे का ढेर यथावत पड़ा है। कर्मचारी योगेश बेले ने बताय कि वे संस्था के साथ 2018 से नगरपालिका में काम कर रहे हैं। जब भी वो ईपीएफ का मुद्दा उठाते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर उन्हें काम से निकालने की धमकी देता है। विजय जैसवाल का कहना है कि ठेकेदार का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी मांग सिर्फ

ईपीएफ और अनुभव प्रमाणपत्र की है। जिस पर कंपनी हमें धमकाकर चुप करवाना चाहती है। गौरतलब रहे कि बैतूल में सफाई व्यवस्था के लिए अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति का ठेका सोम सांई विजन को दिया गया है। कंपनी की ओर से नियुक्त कचरा गाडियों के ड्राइवर, हेल्पर और आईसी मेंबर का कहना है कि कोरोना काल के समय उनके कई साथियों को ईपीएफ का लाभ दिया गया था। इसको लेकर उनसे भी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अब उन्हें ईपीएफ नहीं दिया जा रहा है। इधर कंपनी के डायरेक्टर संतोष अग्रवाल ने बताया कि कर्मचारियों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में पीएफ शामिल नहीं था। उनकी ओर से लिए गए ठेके में पीएफ देना जरूरी नहीं है।

इनका कहना है -

नगरपालिका के स्थाई कर्मचारी नगर में सफाई व्यवस्था बनवा रहे हैं। सोम सांई विजन का कार्यकाल 10 दिन का ही बचा है। 2017 में ये संस्था सफाई के लिए नियुक्त की गई थी। उस समय ईपीएफ की शर्त शामिल नहीं थी। ईपीएफ 2020 में शुरू हुई है। नगर पालिका ने नए टेंडर में हमने ईपीएफ का प्रावधान रखा हुआ है।

-ओमपाल भदौरिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

जानलेवा हमले के अपराधियों पर जिलाबदर और रासुका की कार्रवाई की मांग

युवा आदिवासी विकास संगठन ने शहर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

बैतूल। युवा आदिवासी विकास संगठन ने शहर में बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए मंगलवार रात 6 आदिवासी मजदूरों पर किए गए जानलेवा हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह इवने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी श्रीमती कमला जोशी को ज्ञापन सौंपा। जितेंद्र सिंह इवने ने बताया कि 15 अक्टूबर की रात शहर के आदतन अपराधियों ने आदिवासी समाज के गरीब मजदूर तबके के युवकों और बुजुर्गों पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की, साथ ही लूटपाट और वाहनों की तोडफ़ोड़ भी

की। हमले में कई आदिवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वरिष्ठ समाजसेवी हेमंत सरियाम ने मांग की है कि इन अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि आदिवासी समाज के मजदूर और छात्र-छात्राएं सुरक्षित रह सकें। संगठन के जिला उपाध्यक्ष अविनाश धुर्वे ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी हेमंत सरियाम, अविनाश धुर्वे, रामदास उइके, कमलेश पांसे, अमित उइके, उत्तम वरकड़े, राकेश उइके, राजकुमार उइके और सोहन वाड़ीवा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

यूरिया-डीएपी के साथ थोपे जा रहे अनचाहे उत्पाद

उर्वरक विक्रेताओं ने उपसंचालक को सौंपा ज्ञापन

बैतूल। जिला खाद, बीज, दवा विक्रेता संघ ने रासायनिक उर्वरक प्रदायक कंपनियों की मनमानी का विरोध करते हुए उपसंचालक (कृषि) किसान कल्याण एवं कृषि विकास बैतूल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उर्वरक विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि कंपनियां यूरिया और डीएपी जैसे मुख्य उर्वरकों के साथ अपने अन्य उत्पाद, जैसे जिंक, सल्फर, सागरिका, माइक्रोराइझा, पी.डी.एम., नैनो डीएपी, सिटी कम्पोस्ट, पोली हैलाइट, कीटनाशक बीज, आदि जबरदस्ती टेगिंग कर रही हैं। विक्रेताओं ने बताया कि अगर वे कंपनियों के इन अतिरिक्त उत्पादों को नहीं खरीदते हैं, तो उन्हें यूरिया और डीएपी जैसी

जरूरी खादें देने से इनकार किया जाता है। इस कारण विक्रेताओं को मजबूरी में टेगिंग किए गए उत्पाद भी खरीदने पड़ते हैं, जिसे आगे किसानों को बेचना पड़ता है। यह स्थिति किसानों और विक्रेताओं के बीच वाद-विवाद की वजह बनती जा रही है। विक्रेताओं का कहना है कि किसानों को जबरन दिए गए उत्पादों की गुणवत्ता और जरूरत पर सवाल उठते हैं, जिससे उनके रिश्ते बिगड़ते हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विपणन संघ, एम.पी. एग्रो और सोसायटियों को बिना किसी टेगिंग के यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है,

जबकि निजी विक्रेताओं को इन उर्वरकों के साथ अनचाहे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा, विपणन संघ और सोसायटियों को एफ.ओ.आर. (फ्री ऑन रोड) व्यवस्था के तहत बिना अतिरिक्त परिवहन और हम्माली शुल्क के उर्वरक उनके गोदाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। जबकि निजी विक्रेताओं को एक्स-गोदाम से उर्वरक उठाने के लिए अतिरिक्त भाड़ा और हम्माली शुल्क वहन करना पड़ता है। बैतूल जिले के उर्वरक विक्रेताओं ने सरकार और कृषि विभाग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कंपनियों की दोहरी नीति को समाप्त करने की अपील की है ताकि विक्रेताओं और किसानों दोनों को राहत मिल सके।

संस्कारों का निर्माण बाल्यकाल से ही होता है: दिनेश जी तेजरा

धार नगर के बाल पथ संचलन में बाल स्वयंसेवकों का पथ संचलन ऐतिहासिक और विराट रूप में निकला

धार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों का पथ संचलन ऐतिहासिक और विराट रूप में निकला । यह संचलन धार के लाल बाग से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्ग से गुजर कर पुनः लाल बाग पर समापन हुआ। सभी स्वयंसेवक संघ की गणवेश धारण करते हुए अनुशासन के साथ कदमताल मिलाते हुए संचलन में चल रहे थे । संचलन में बाल स्वयंसेवकों की विभिन्न वाहिनियां पंक्ति के रूप में चल रही थी । संचलन के पूर्व मंच पर अध्यक्षता उदय वडनेरकर(अधिवक्ता) ने की एवं साथ ही मंच पर जिला बाल कार्य प्रमुख कुंदन वाघेला,नगर कार्यवाह गोपाल डोड आसीन हुए ।

मंचासीन अध्यक्ष ने कहा कि यह बचपन की उम्र में संघ से जुड़ना बहुत अच्छा है । ये उम्र संघ से जुड़ने के लिए एक दम सही उम्र है । वही धार विभाग प्रचारक दिनेश तेजरा ने अपने व्यक्तत्व में कहा की हम अपने दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। हमारे सभी महापुरुष बड़े होकर राष्ट्रभक्त नहीं बने , बचपन से ही राष्ट्रभक्त थे । उन सभी के अंदर संस्कारों का निर्माण बाल्यकाल से ही होने लगा था । इसी कारण वे अपने जीवन में महापुरुष कहलाए । संघ की स्थापना सन 1925 में हुई । संघ के प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने आप जैसे बाल स्वयंसेवकों को लेकर शाखा लगाई और देखते ही देखते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़े संगठन के रूप में दिखाई देता है । ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डॉक्टर साहब बचपन से ही राष्ट्र भक्ति की भावना से ओत प्रोत थे । और अगर हम सभी को मिलकर राष्ट्र का उत्थान करना है तो प्रत्येक बाल को संघ में आना होगा । इसलिए प्रत्येक बाल को संघ के लगने वाली शाखा में आना चाहिए ताकि उसका स्वयं के जीवन में व्यक्तिगत निर्माण भी हो सकेगा और साथ ही साथ राष्ट्र कार्य में भी वो अपनी आहुति दे सकेगा।

दल बना आकर्षण का केंद्र...

संघ के संचलन में बजने वाला घोष सभी स्वयंसेवक को उत्साहित कर रहा था । नगरवासी भी घोष की धुन को देखकर प्रभावित नजर आए । अलग अलग प्रकार की रचनाएं स्वयंसेवक द्वारा कही दिनों के अभ्यास के बाद बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ पूरे संचलन में एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी ।

20 अक्टूबर को निकलेगा तरुण व्यवसायी शाखाओं का बस्ती संचलन

बाल संचलन के पश्चात धार की 14 बस्तियों का अपनी अपनी बस्ती के नियत स्थान से 20 अक्टूबर को प्रातः9 बजे संचलन निकाला जाएगा । जिसको लेकर वृहद स्तर पर तैयारी की जा रही है । जानकारी नगर कार्यवाह गोपाल डोड ने दी।

अमृत संचय टीम ने बीसाखेड़ी के जल स्तोत्रों का किया निरीक्षण

देवास। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता एवं सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में जिले में अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अब मूर्त रूप लेने लगा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जिले में अमृत संचय अभियान की टीम का कारवाँ अब पानी बचाने का संदेश लेकर जिले में गाँव-गाँव पहुँचने लगा है। जहां ग्रामीण जन भी इस अभियान से जुड़कर जल संचय के लिए वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम, बोरी बंधान निर्माण कार्य कर रहे हैं। अमृत संचय अभियान की टीम द्वारा सोनकच्छ ब्लॉक के ग्राम बीसाखेड़ी में अभियान के अंतर्गत बनाए गए बोरी बंधान एवं वाटर हार्वेस्टिंग का भौतिक सत्यापन किया गया। अमृत संचय टीम ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में इस बार अपेक्षाकृत कम बारिश हुई। न तो तालाब भर सके और न ही कुओं के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई। कुछ तालाब तो अब तक सूखे ही पडे हैं। ग्रामवासियों ने स्थिति को भांपते हुए न केवल जलसंचय का संकल्प लिया बल्कि भविष्य की तैयारियो में भी जुट गये। अमृत संचय अभियान की टीम आज सोनकच्छ तहसील के बीसाखेड़ी पंचायत क्षेत्र में पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्राम पंचायत बीसाखेड़ी सरपंच जितेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में इस बार अपेक्षाकृत कम बारिश हुई। न तो तालाब भर सके और न ही कुओं के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हुई। कुछ तालाब तो अब तक सूखे ही पडे हैं। बावजूद इसके ग्रामवासियों ने जलसंचय अभियान के तहत न सिर्फ अपनी अपनी छतों पर रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की पहल की है बल्कि जहाँ-जहाँ सम्भव हो सका रीचार्ज पिट का निर्माण भी कर लिया है। पंचायत सचिव धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि पंचायत भवन की छत के साथ स्कूल की छत और सामुदायिक भवन की छत के पानी को जमीन मे उतारने के लिए रीचार्ज पिट तैयार कर लिए गए हैं जिससे 45000 स्क्वेयर फीट की छतों के पानी का संचय किया जा सकेगा।

अमृत संचय अभियान की टीम के श्री मोहन वर्मा, श्री महेश सोनी तथा श्रीमती शर्मिला ठाकुर ने क्षेत्र के सूखे पड़े तालाब और नालों का मुआयना किया और मौके पर उपस्थित इंजीनियर श्री प्रदीप जोशी संग आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तार से बात की। जोशी ने बताया कि अल्प वर्षा के कारण सूखे पड़े तालाब और नालों मे पानी ही नहीं होने से बोरी बंधान सम्भव नहीं हो सका। इस दौरान श्री मोहन वर्मा ने माता मंदिर परिसर में एकत्रित ग्राम वासियों से भी बात की और जलसंचय की जरूरत और गंभीरता समझाई जिसपर ग्राम वासियों और सरपंच ने कुछ घरों को रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए चिन्हित कर शीघ्र ही टीम को फिर से आने का आग्रह भी किया।

डीईओ नर्मदापुरम के खेल विभाग का एक और कारनामा

- केसला में जनजातीय विभाग के बच्चों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार नहीं...!

नर्मदापुरम- संजीव डे राय

शिक्षा विभाग खेल अंशदान के रुप में सभी स्कूलों से राशि लेता है और प्रायः सभी स्कूल छात्र छात्राओं से खेल फीस पालकों से वसूल लेता। लेकिन छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली फीस के ऐवज में ऐसे कितने स्कूल है जो छात्र-छात्राओं को खेल का लाभ दे रहे हैं। कितने स्कूलों के पास खेल मैदान है। शिक्षा विभाग यह बताने में कतरा जायेगा क्योंकि इसकी जानकारी उसके पास नहीं न वो इस जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करता है। शिक्षा विभाग खेल के नाम पर खुद खेल खेलता है। विभागीय खेल अधिकारी तो बच्चों की डाइट तक का पैसा पचा लेते, फिर जो प्रतियोगिता एक दिन में खत्म हो जाती दो दिन का देयक निकाला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की तो इसे लेकर हालत और खराब बताई जाती है। विभाग केसला ब्लॉक के सभी प्राइवेट स्कूल से खेल अंशदान की राशि लेता है,पर किसी को भी प्रतियोगिता में सम्मिलित नही किया जात, और न ही केसला शिक्षा अधिकारी को प्रतियोगिता की जानकारी दी जाती है। केसला ब्लॉक के सभी स्कूल जनजातिय विभाग में आते लेकिन प्राइवेट स्कूल के जनजातिय विभाग खेल विभाग प्रतियोगिता में भाग नही ले सकते। इसके लिए शिक्षा विभाग जनजातीय विभाग के प्राइवेट स्कूल को प्रतियोगिता में सम्मिलित करने के निर्देश है, फिर निर्देश होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम के खेल विभाग ने इन विद्यार्थियों के लिए कोई व्यवस्था नही की। डीपीआई ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के व्यवस्था की है, ऑनलाइन होने के कारण खिलाड़ियों को संकुल को फारवर्ड करना पड़ता है पर इन स्कूलों की कोई कार्य व्यवस्था नही है इस कारण इन स्कूलों के खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता में भाग नही ले पाए। नर्मदापुरम के केसला ब्लाक के सभी निजी विद्यालयों से जिला शिक्षा विभाग नर्मदापुरम द्वारा खेल अंशदान नियमित लेता है परंतु उन्हें खेल विभाग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिला खेल अधिकारी से पूछे जाने पर बताया जाता है कि केसला ब्लाक के सभी स्कूल जनजातीय विभाग में आते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि जनजातीय विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में केसला ब्लॉक में आने वाले प्राइवेट स्कूलों को शामिल नहीं किया जाता परंतु क्रीड़ा शुल्क जिला शिक्षा विभाग नर्मदा पुरम द्वारा लिया जाता रहा है इस संदर्भ में आदिवासी समाज एवं जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासी अभिभावकों ने क्रीडा शिक्षक रहे एवं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री चेतन राजपूत से जब आदिवासी एवं जनजातीय लोगों के बच्चे जो की केसला ब्लाक के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किए जाने पर बात रखी गई तब उन्होंने यह बात आयुक्त आलोक खरे के सामने रखी तब आयुक्त से जनजातीय विभाग के प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता में सम्मिलित किए जाने के निर्देश एवं एक पत्र जारी किया गया बावजूद इसके केसला ब्लाक जनजातीय विभाग में आने वाले प्राइवेट स्कूल के बच्चे प्रतियोगिता से वंचित रह गए शिक्षा विभाग नर्मदा पुरम द्वारा कोई जरूरी उपाय ना ही कोई प्रयास नहीं कोई उचित जानकारी प्रदान की गई इस प्रकार की अनियमित के चलते आदिवासी एवं जनजातीय लोगों के बच्चों का खेल प्रतियोगिताओं में सम्मिलित न होने के कारण आदिवासी क्षेत्र के बच्चे एवं उनके परिवारजन बहुत दुखी है और उन्होंने कहा कि क्या हमारे बच्चों को किसी प्रतियोगिता में खेलने का अधिकार नहीं है. यहां उल्लेखनीय है कि जिला खेल अधिकारी खुद उक्त पद के लिए पात्र नहीं होने के बावजूद राजनीतिक दबाव में पद पर है और जिस संभागीय मुख्यालय के जुमेराती स्कूल में खेल शिक्षक का पद स्वीकृत ना होने के बाद खेल शिक्षक के रूप में वर्ष 2012 से पदस्थ है वह कैसे..? जबकि संभागीय मुख्यालय की कई उमावि विधालय में वर्षों से खेल शिक्षक नहीं है, पद स्वीकृत ना होते हुए भी खेल शिक्षक के पद पर नियुक्ति बिना मोटी सेवा के सम्भव है क्या..?

पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने पर ग्रेसियस कॉलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास वालों को हुई सजा

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/ ने बताया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2020 को फरियादी विमल चैधरी ने उसके मित्र किषोर पटेल, राजेश पांचाल, कैलाश जायसवाल के साथ आरक्षी केन्द्र कोतवाली देवास पर उपस्थित होकर इस आषय की मौखिक रिपोर्ट की वर्ष 2014 में ग्रेसियस कॉलोनाईजर इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी देवास, आयकन मल्टी कलानी बाग देवास स्थित ऑफिस चिटफण्ड कंपनी ग्रेसियस कालोनाईजर इंडिया लिमिटेड देवास के डायरेक्टर लखन जायसवाल व धर्मेन्द्र ठाकुर देवास ने दिनांक 10.01.2014 को उनको कार्यालय में बुलाया और कहा कि यदि वे उनकी कंपनी में एक लाख रूपये जमा करेंगे और 05 साल बाद डबल मिलेंगे उन्होंने और भी फायदे बताये जिस पर फरियादी व उसके उक्त सभी मित्रों ने उक्त कंपनी में आर.डी व एफडी खाते खुलवाये। फरियादी ने एक लाख रूपये की एफ.डी.क्रं एल-810100006332 में दिनांक 30.04.2015 करवायी जिसमें उसे 30.10.2020 को 2,00,000/-रूपये की राषी मिलनी थी। फरियादी ने स्वयं के नाम से दो आरडी खाते तथा उसकी पत्नी व बेटे के नाम से एक-एक आरडी खाता खुलवाया, जिसमें कुल 1,58,500/- रूपये की राषि जमा की। उसके मित्र व अन्य लोगो ने एफडी व आरडी खाते खुलवाये किन्तु उनकी परिपक्वता होने पर भी दोनों अभियुक्तगण ने एफडी व आरडी का राशि भुगतान नही किया और उक्त राशि का गबन कर लिया। उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास (समक्षः-श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार साहब) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण लखन पिता नारायण जायसवाल उम्र 38 वर्ष, निवासी मिश्रीलाल नगर देवास एवं धर्मेन्द्र सिंह पिता जगन्नाथ ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बनखेड़ा जिला सिहोर को दोषी पाते हुये भादंस की धारा 420 में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000-50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 406 में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000- 50000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 120-बी में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000- 50,000/-रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 6(1) म.प्र.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में 04-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 1,00,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री जगजीवनराम सवासिया, विषेष लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चैहान का सराहनीय सहयोग रहा।

मीना बाजार में अखिल भारतीय मुशायरा का आयोजन 19 अक्टूबर को

देवास। नगर पालिक निगम देवास द्वारा आयोजित 88 वीं दशहरा कृषिकला एवं औद्योगिक प्रदर्शनी 2024 (मीना बाजार) के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्टुबर को रात्रि 9 बजे से अखिल भारतीय स्तर मुशायरे का आयोजन किया गया है। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुवें बताया की आयोजित किये जा रहें अखिल भारतीय मुशायरें में ताहिर फारज रामपुर, अज्म शाकरी ऐटा, हाशिम फिरोजाबादी फिरोजाबाद, सिकन्दर हयात गडबड रूडकी, हामीद भुसावली भुसावल, डॉ. रानी रूही जबलपुर, अनित मुकाती धार, वसीम राजुपूरी राजुपूर, टिपीकल जगदीयाली हैदराबाद, अनवर कमाल बिहार, ताहीर सउद युपी, डॉ. जलीलुर रहमान बुराहनपुर, करीमुद्दीन मुम्बाई ,सज्जाद झनझट उत्तराखंड, अल्तमश तालिब नान्देड, रजा खतोलवी खतोली, नूर धोलपुरी धोलपुर, जमील असगर महाराष्ट्र, हनीफ राही शाजापुर,आदि शिरकत करेंगें महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के नागरिकों से अनुरोध किया है कि आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय मुशायरा को सुनने अवश्य पधारें।

वाल्मीकि जयंती पर निकली शोभायात्रा का किया भव्य स्वागत

नवल गिरी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन

बैतूल। वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर समरसता सेवा संस्थान द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मार्गदर्शन महामंडलेश्वर नवल गिरी महाराज ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शर्मा के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष किशोर धोटे के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभायात्रा सुभाष स्कूल के पास से शुरू होकर कोठी बाजार और नेहरू पार्क होते हुए ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुई। पूरे मार्ग पर भक्तों का उत्साह देखने लायक था। शोभायात्रा के दौरान लोगों ने जगह-जगह श्रद्धालुओं का स्वागत कर महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया। इस अवसर पर शुभनीत सरसोदे मोनू पाल, किशोर धोटे, रविंद्र धोटे, मिथिलेश चौहान, मनोज पाटिल, बाबूराव गायकवाड, गौतम यादव, आकाश आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजन को भव्य रूप दिया। शोभायात्रा में भगवान वाल्मीकि के जीवन और उनके महान उपदेशों का विशेष उल्लेख किया गया। मार्गदर्शन के लिए नवल गिरी महाराज का आभार जताया गया और यात्रा के माध्यम से समाज में एकता और समरसता का संदेश फैलाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए यह शोभायात्रा पूरी गरिमा और भव्यता के साथ सम्पन्न हुई।

नकारात्मक भाव को कम करने,जीवन में खुशहाली लाने के साथ आनंदमयी जीवन के उद्देश्य से ही आनंद विभाग

सुबह सवेरे सोहागपुर

नकारात्मक भाव को कम करने,जीवन में खुशहाली लाने के साथ आनंदमयी जीवन के उद्देश्य से ही मध्यप्रदेश आनंद विभाग का गठन हुआ है। इसी तारतम्य में एक दिवसीय अल्पविराम परिचय कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओ के साथ जनपद सभागार में जनपद पंचायत सीईओ संजय अग्रवाल के आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर गणेश कनाडे ने आनंद विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो के माध्यम जानकारी दी कि अल्पविराम हमारी स्वयं से स्वयं की मुलाकात का एक माध्यम है7 मध्यप्रदेश शासन ने नागरिकों में नकारात्मक भाव को कम करने के साथ जीवन में खुशहाली लाने तथा परिपूर्ण आनंदमयी जीवन जीने के लिए आनंद विभाग का गठन किया गया है। इससे जुड़कर हम अपने भीतर अपनी अप्रत्यक्ष कमियों की पहचान कर उनमें सुधार कर सकते हैं। अपने जीवन में निरंतर इस्तेमाल किया जा सकता है। जीवन का लेखा जोखा

के प्रश्नों के माध्यम से उपस्थित सभी नागरिकों को अपने आप से जोड़ने का प्रयास करके प्रेरित किया गया। ताकि हम दूसरों को कुछ भी बोलने से पहले खुद अपने अंदर भी एक बार जरूर झांके कि कहीं बुराई का कोई अंश हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है। इसी क्रम में मास्टर ट्रेनर सुमनसिंह ने रिश्तों के महत्व पर प्रकाश डालते कहा सबका ध्यान रिश्तों का चार्ट बनाकर खींचा कि हम किस तरह से समझ सकते हैं। कि हमारी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं ।उनमें कौनसा रिश्ता सबसे प्यारा है कौन सा रिश्ता हमारा बिखरा हुआ है। जब कोई बिखरा हुआ रिश्ता हमको नजर आए । तब किस तरह से हम अपने रिश्ते को भी सुंदर बनाकर अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। अल्पविराम के माध्यम से सुधार किए जाने के माध्यम से आपने अनुभव साझा करते कहा कि अल्पविराम की मदद से माफी मांग कर , दिल से माफ करके अपनी और से पहल कर बिगड़े रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। ताकि रिश्ते खतम होने से पहले उनको बचा लें। इसी अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव सुनाए। तथा आनंदम सहयोगीयों ने कहा कि आनंद विभाग के अल्पविराम कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उपस्थित जनों ने कहा कि उक्त कार्यक्रम समाज के लिए उपयोगी आवश्यकता है। आशा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया आगे का जीवन हम अल्पविराम के सहयोग करके और बेहतर बनाएंगे। इस अवसर पर पर संजय नागोरिया, राजेंद्र कुशवाह, स्तुति मालवीय ,स्वास्थ्य विभाग मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक शैलेंद्र शुक्ला के साथ आनंद विभाग नर्मदापुरम टीम ने अल्पविराम कार्सेयक्रम में सहयोग उल्लेखनीय रहा।

विश्व छात्र दिवस पर व्याख्यानमाला का आयोजन

धार। श्री राजेन्द्र सूरी -शासकीय महाविद्यालय, सरदारपुर -राजगढ़ में स्वामी विवेकानंद कॅरियर प्रकोष्ठ द्वारा विश्व छात्र दिवस पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया । महाविद्यालय के प्राचार्य ,एल-एस-अलावा ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित रहने हेतु प्रेरित किया। मुख्य वक्ता प्रो-सरिता जैन ने विद्यार्थी जीवन व्यक्ति का गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और उन्होने बताया.गुणैहिं सर्वत्र पदं निधियते (जो गुणवान. है वह उच्च पद प्राप्त करता है) विद्यार्थी जीवन हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, इसे हम जीवन का स्वर्णिम समय कह सकते है। माता, ही बच्चों को उच्च संस्कार, परिश्रम, अनुशासन, संयम ,और नियम के साथ मानवीय गुणों का संचयन करना

सिखाती है । डॉ-रंजना पाटीदार ने विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रो-आर-के-जैन ने भी विद्यार्थियों को उदेश्य के अनुसार कार्य करें पर अपने विचार व्यक्त किये। महाविद्यालय के विद्यार्थियों कोमल परमार ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की ओर इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होते रहना चाहिये। अंजली कुमावत ने कहा कि विद्यार्थी को लक्ष्य के अनुसार तैयारी करना चाहिए । कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया जिसमें लगभग 90 विद्यार्थी उपस्थित रहें। कार्यक्रम में महाविद्यालय का समस्त स्टॉफ, डॉ-ममता दास, डॉ-राकेश शिन्दे, डॉ-रीना खाण्डेकर, स्नेहलता मण्डलोई, लालिमा , डॉ मोहित सिंह चौहान, विजयाराजे दरबार, महेन्द्र अलावा, दिपेश डांगी , महेश उपाध्याय, बिन्दु गोखले, अजय राठौर, इन्दरचन्द झुन्झे ,वं महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहें। कार्यक्रम का संचालन डॉ-डी-,एस-मुजाल्दा ने किया। आभार प्रो-सुरेन्द्र रावत ने माना।

सत्ता का सर्कस

दिनेश गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

भाजपा विधायकों के असंतोष का नेतृत्व करने वाला चेहरा किसका?

वल्लभ भवन यानी मंत्रालय जब से तीन अलग-अलग भवनों में बंट गया तब से यहां गहमागहमी की जगह नीरसता और सन्नाटे में बदल गई है। मंत्रालय के पुराने भवन की चमक भी खत्म हो चुकी है। जो दो नई इमारत एनेक्सी के तौर पर खड़ी की गई हैं वे किसी महानगर के नामी अस्पताल की तरह दिखती हैं। इन भवनों में नजर आने वाले चेहरे थके हुए और उदास दिखते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को हैदराबाद जाना था। वहां उन्हें निवेशकों से बातचीत करना थी। रोड शो भी प्लान किया गया था। 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित रीजनल इन्डस्टीज कॉन्क्लेव की तैयारी का यह हिस्सा थी। मुख्यमंत्री ने अपना हैदराबाद प्रवास क्यों टाला इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई कारण सामने नहीं आया। सोमवार को इंदौर को जो घटनाक्रम था,उसे साधारण कतई नहीं माना जा सकता। राज्य के सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग्स माफिया को लेकर जो बयान मुख्यमंत्री के सामने सार्वजनिक मंच से दिया,उसकी धमक दूर तक सुनाई दी है।

इंदौर में मुख्यमंत्री ने बड़ा कार्यक्रम किया था। शहरवासियों को सोमवार को एक साथ 4 फ्लाईओवर की सौगात मिली। खजराना और लव कुश फ्लाईओवर की एक-एक लेन तो भंवरकुआं और फूटी कोठी ब्रिज की दोनों लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इन ब्रिज के शुरू होते ही इंदौर ने एक और कीर्तिमान रच दिया। लक्ष्य से एक महीने पहले ही इन्हें तैयार कर दिया। दावा है कि ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ। इंदौर के लोग इस उपलब्धि से उत्साहित हैं। लेकिन,शहर में ड्रग्स सप्लायरों के पैर जमाने से हर इंदौरी के चेहरे पर चिंता देखी जा सकती है। सभी को यह धुकधुकी लगी रहती है कि कहीं उनका कोई परिजन ड्रग्स की लत का शिकार न हो जाए। इंदौरी ड्रग्स के धंधे पर नकेल डालने हर नेता की देहरी को छू चुके हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भी अपने स्तर पर पुलिस अफसरों को कई बार चेता चुके हैं। लेकिन,कारोबार है कि रूकता नहीं। शायद इस कारण ही उन्हें मजबूरी में सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि चोर की मां को पकड़ो। इन शब्दों के जरिए विजयवर्गीय ने एक बड़ा राजनीतिक हमला मुख्यमंत्री पर बोला। दो कारण हैं इसे बड़ा राजनीतिक हमला मानने के, पहला मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग के मुखिया हैं। दूसरा वे इंदौर के भी प्रभारी हैं। यदि मुख्यमंत्री के प्रभार वाले जिले में ही नशे का कारोबार चल रहा हो तो सार्वजनिक मंच से जन प्रतिनिधि का जुबान खोलना मजबूरी हो जाता है। विजयवर्गीय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि- इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं उनके नाम भी मुझे पता है।

विजयवर्गीय ने कहा, मेरे पास ड्रग्स बेचने वालों के नाम आ गए हैं। भोपाल से अधिकारियों को राजस्थान पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस सार्वजनिक बयान के बाद किसी अफसर ने उनसे मिलकर जानकारी ली हो, लगता नहीं है। लेकिन, मुख्यमंत्री का हैदराबाद दौरा निरस्त होने से हलचल जरूर बढ़ी। शाम होते होते यह खबर भी आई कि मुख्यमंत्री निवास में कोई बैठक बुलाई गई है,जिसमें गृह विभाग के अफसर भी हैं। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीटों के लिए भी उप चुनाव की घोषणा कर दी। यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री निवास की यह बैठक इन चुनाव को लेकर बुलाई गई हो?

इन दो सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए सोमवार को ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी भाजपा कार्यालय पहुंचे। बैठक में विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम तय हुआ। वहीं, बुधनी से 4 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। इनमें वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह, पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और पूर्व विधायक राजेंद्र चौहान के नाम हैं। शिवराज सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बुधनी विधानसभा सीट खाली है। लोगों की दिलचस्पी विजयपुर से ज्यादा बुधनी का उम्मीदवार जानने में है। बुधनी विधानसभा शिवराज सिंह चौहान की सीट है। चौहान के लोकसभा में चले जाने के बाद पार्टी किसे मौका देती है, उनके पुत्र या समर्थक को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही तय करना है। यह नीतिगत मामला है।

सोमवार को ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में गहमागहमी की एक वजह नाराज विधायक थे। पार्टी ने तीन नाराज विधायकों को चर्चा के लिए बुलाया था। उनमें से दो विधायक बृजबिहारी पटैरिया और प्रदीप लारिया भोपाल आए। संगठन नेताओं से चर्चा के बाद लारिया ने चुप्पी साध ली जबकि पटैरिया बोले - अब बात खत्म हो गई है। प्रदीप पटेल सोमवार को नहीं आ सके। उन्होंने संगठन नेताओं से कहा कि इतनी जल्दी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। वे बाद में आकर नेताओं से मिलेंगे। मऊगंज के विधायक पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे एसपी के पैरों में गिर कर खुद की सुरक्षा की मांग करते दिख रहे थे?

पटेल का आरोप है कि यह जिला पूरी तरह से नशाखोरी की चपेट में है। कैलाश विजयवर्गीय का हमला भी नशे और ड्रग्स को लेकर ही था। लेकिन,उनकी बात का जवाब मुख्यमंत्री ने मंच से ही दे दिया था। इस कारण शायद किसी को भी विजयवर्गीय से बात करने की जरूरत नहीं लगी। वैसे भी किसी मंत्री द्वारा उठाए गए मामले का हल मुख्यमंत्री ही चर्चा से निकाल सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयवर्गीय को मंच से ही यह आश्वासन दिया कि-नशे का कारोबार करने वालों को बख्शेंगे नहीं। पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है।

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा (वीडी शर्मा) मंगलवार को इंदौर में थे। मंगलवार को भाजपा की सदस्यता अभियान का समापन था। पार्टी ने डेढ़ करोड़ सदस्य बनने का दावा किया है। इनमें एक करोड़ चालीस लाख सदस्य ऑनलाइन बनना बताया गया है। पार्टी अब सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान चलाएगी। पार्टी के इस अभियान पर वरिष्ठ नेता अजय विश्नोई ही सवाल खड़े कर रहे हैं? बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि -मेरे पास एक फोन आया कि आप सदस्यता अभियान का ठेका हमें दे दीजिए। ये एक एजेंसी का कॉल था। ऐसे तो लोग पैसों के दम पर सदस्य बढ़वाकर खुद को बड़ा नेता दिखाएंगे। अजय विश्नोई ने आगे लिखा- भाजपा के सदस्य बनवाने है तो पैसा खर्च कीजिए। जाहिर है ऐसी और भी एजेंसी होंगी। जिनकी सेवाएं लेकर गणेश परिक्रमा करने वाले आधारहीन नेता संगठन की नजर में बड़े बनने की कोशिश में लगे होंगे। मैंने पहले भी कुछ लोगों को विज्ञापन छपवा कर, नेताओं के सम्मान, स्वागत और घर के भीतर अपनी सेवाएं देकर नेता बनते देखा है। इस बार यह नया ट्रेंड देखने में आ रहा है। जहां पैसा खर्च करके अपने अकाउंट से बनने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लोग बड़ा नेता बनने में लगे हैं। इस गिरावट पर हम पुराने कार्यकर्ता अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।

अजय विश्नोई पार्टी के उन नेताओं में हैं जो गलत को गलत कहने का साहस आज भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने जबलपुर से पार्टी उम्मीदवार की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। विश्नोई की तरह ही वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव भी गलत का विरोध करने सबसे आगे दिखते हैं। विधायक बृजबिहारी पटैरिया के साथ भी भार्गव खड़े हुए दिखाई दिए थे। भार्गव, सोमवार को भोपाल में थे। भोपाल में उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने मुलाकात की थी। इनके अलावा शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भी उनसे मुलाकात की थी। गोपाल भार्गव प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। 2003 के बाद यह पहला मौका है जब भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में उन्हें नहीं रखा गया है। अजय विश्नोई, शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं पा सके थे। डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी में वरिष्ठ विधायकों में दबी हुई नाराजगी देखी जा रही है। दमोह के विधायक जयंत मलैया और होशंगाबाद के विधायक सीताशरण शर्मा भी ऐसे ही विधायकों में हैं। पिछले दिनों सीताशरण शर्मा ने इटारसी के बाजार और रेल्वे स्टेशन मार्ग के अतिक्रमण को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की थी। शर्मा ने कहा था कि मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना होगा।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह से एक-एक कर विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, उसमें यह सवाल भी बड़ा है कि इन विधायकों के असंतोष का नेतृत्व कौन कर रहा है? सरकार के भीतर सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है। कैलाश विजयवर्गीय। सरकार के बाहर असंतोष का चेहरा गोपाल भार्गव को माना जा रहा है। भार्गव ही वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खुलकर बात कर सकते हैं। जयंत मलैया,अजय विश्नोई या सीताशरण शर्मा की सियासत नेतृत्व की नहीं रही है। यहां यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विरोधी एकजुट होते हैं या नहीं? शिवराज सिंह चौहान के विरोधी कभी एक नहीं हो पाए थे। इसी कारण वे सबसे लंबी पारी खेलने में सफल रहे थे।

भोपाल में चक्कर खाकर बेहोश हुई एएनएम नर्स, मौत

- **डॉक्टरों ने जताई कार्डियक अरेस्ट की आशंका,पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा, 7 महीने पहले ही हुई थी शादी**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक एएनएम नर्स की मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि बाथरुम से नहा कर निकली मृतका अचानक चक्कर खाकर गिरी और बेहोश हो गई। परिजन उसे तत्काल जिंदल अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत होने का अंदेशा जताया है।

जानकारी के अनुसार अयोध्या नगर में जिंदल अस्पताल के पास रहने वाली शीतल बैरागी (32) की मौत हुई है। शीतल वार्ड 68 स्थित आईटीआई डिस्पेंसरी में 2021 से एएनएम नर्स के रूप में काम कर रहीं थीं। मूलतः बैतूल की रहने वाली शीतल की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी। अयोध्या नगर में जिंदल अस्पताल के पास रहने वाली शीतल बैरागी आईटीआई डिस्पेंसरी में 2021 से एएनएम नर्स के रूप में काम कर रही थी। अयोध्या नगर पुलिस के अनुसार शव को पोस्टमॉर्ट्म के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया था। यहां पीएम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। हालांकि पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। शीतल के भाई दीपक ने बताया कि अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसे शायद हार्ट अटैक आया था। हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी।

इस उम्र में बहुत कम चांस होता है कि दिल की धड़कन अनियमित हो, मगर ऐसा हो भी सकता है। कई बार एक दम कोलेप्स के चांस होते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत चक्कर आते हैं, या इससे जुड़े कुछ और लक्षण हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो बीपी-पल्स चेक करें और तुरंत ही सीपीआर दें। क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में मूव करने में जो समय लगाते हैं, वह समय मरीज की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी समय होता है। इस केस को देखा जाए तो आशंका जताई जा सकती है कि यह दिल की धड़कन की अनियमितता के कारण हुआ होगा। आनुवांशिकी कारण भी हो सकता है।

- डॉ. किस्ले श्रीवास्तव, कॉर्डियोजॉलिस्ट,सेज अपोलो अस्पताल

होशंबागाद रोड का 30 प्रतिशत ट्रैफिक डीआरएम तिराहे पर शिफ्ट

भोपाल में 8 महीने बाद खुला रास्ता; साकेतनगर-शक्तिनगर के लोगों को भी बड़ी राहत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के डीआरएम तिराहे का रास्ता खुलने से होशंगाबाद रोड का करीब 30 प्रतिशत ट्रैफिक यहां शिफ्ट हो गया है। गुरुवार को रास्ते की बेरिकेडिंग पूरी तरह से हटा दी गई। यह रास्ता करीब 8 महीने बाद खुला है। इससे करीब 5 लाख आबादी को राहत मिली है। अब साकेत नगर और शक्तिनगर के अंदरुनी रास्ते से भी गाड़ियां नहीं गुजरेगी। वहीं, एम्स जाने के लिए राह आसान हो गई है। गुरुवार को पूरी तरह से रास्ता खुलने से दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। रास्ता बंद होने से कारोबार खासा प्रभावित हो रहा था। कइयों ने तो दुकानें बंद कर दी थी, क्योंकि यहां इक्का-दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे थे। ऑटो चालक मो. महफूज अली ने बताया, रास्ता खुलने से बड़ी राहत मिली है। अब ज्यादा फेरा नहीं लगेगा। इससे यात्रियों से भी कम किराया वसूलेंगे। डीआरएम तिराहे का रास्ता गुरुवार को पूरी तरह से खोल दिया गया। इसके बाद लोगों को आने-जाने में आसानी हो रही है।

रास्ता खुलने से यह फायदा भी

एम्स जाने की राह आसानः एम्स हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ता था। बाहर से आए लोग तो राह भटक जाते थे, लेकिन अब उनकी राह आसान हो गई है। एमपी नगर से आईएसबीटी, सांची, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होते हुए लोग वीर सावरकर सेतु से नीचे से एम्स जा सकते हैं।

कारोबार फिर से होगाः यहां पर 50 से अधिक दुकानें हैं। रास्ता बंद होने से कारोबार ठप हो गया था। यह दुकानें अब फिर से खुलेगी और अच्छा कारोबार हो सकेगा।

जाम नहीं लगेगाः पीक ऑवर्स के दौरान होशंगाबाद रोड पर जाम की स्थिति बनती थी। एक ही रास्ता होने से हजारों लोग रोजाना एमपी नगर, रानी कमलापति स्टेशन, वीर सावरकर ब्रिज और बीयू के आसपास फंस जाते थे। अब दो रास्ते होने से जाम की स्थिति नहीं बनेगी।

इसलिए बंद किया गया था रास्ता

डीआरएम तिराहे पर मेट्रो की 200 टन वजनी कंपोजिट स्टील ब्रिज की लॉन्चिंग की गई है। इस वजह से मार्च से ही रास्ते पर बेरिकेडिंग कर दी गई थी। जिससे लोग होशंगाबाद रोड होते हुए गुजर रहे थे। रास्ता खुलने से करीब 5 लाख आबादी को आने-जाने में बड़ी राहत मिल गई है। यहां से होशंगाबाद रोड की कॉलोनी, अवधपुरी, बीडीए, एम्स, अलकापुरी, साकेतनगर, रोहितनगर, अमरावतखुर्द समेत सैकड़ों कॉलोनी जुड़ी हैं।

जूनियर ऑडिटर की सैलरी 55 हजार, प्रॉपर्टी 90 करोड़

सफाई में बोला-सिर्फ 12 लाख कैश तो मिला मेरे नाम पर सिर्फ एक मकान

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय में पदस्थ जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी 90 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति का मालिक निकला। लोकायुक्त की 6 टीमों ने बुधवार सुबह 5 बजे हिंगोरानी के बैरागढ़ स्थित आवास समेत 6 ठिकानों पर दबिश दी। देर रात 12 बजे तक चली कार्रवाई में एक-एक किलो से ज्यादा सोने-चांदी के जेवरात, लाखों रुपए कैश, प्रॉपर्टी के कागजात और कई लग्जरी वाहन मिले हैं। नोट इतने थे कि गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी जबकि हिंगोरानी का वेतन 55 हजार रुपए प्रतिमाह था। यही नहीं, उसके पास बड़ी मात्रा में क्रय-विक्रय पत्र और साइन किए हुए ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रमेश हिंगोरानी रियल एस्टेट कारोबार और ब्याज के धंधे से भी जुड़ा है। पत्नी और तीन बेटे योगेश, नीलेश और मोहित के नाम संपत्ति के प्रमाण भी लोकायुक्त टीम के हाथ लगे हैं। आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी के बाद केस दर्ज किया गया था। इसके बाद हिंगोरानी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान बेटे नीलेश के स्कूल में देसी पिस्टल मिली है।

हिंगोरानी ने कहा-

सिर्फ 12 लाख कैश मिला, इतना तो रख सकते हैं

वहीं, रमेश हिंगोरानी ने मीडिया से कहा- लोकायुक्त की कार्रवाई में हमारे घर से सिर्फ 12 लाख कैश मिला है। इतना तो हम रख सकते हैं। कुल 70 लाख के सोने-चांदी के जेवर हैं, जो मेरी बहुओं के हैं। गाड़ी के नाम पर मेरे पास वैगन आर है, जो मैंने 70 हजार रुपए में खरीदी थी।

शरद सुपरमून के साथ गुरुवार को साल की सबसे चमकीली रात थी

पृथ्वी से 3 लाख 57 हजार 364 किमी की दूरी पर होगा चंद्रमा, इस साल की यह सबसे कम दूरी

भोपाल (नप्र)। शरदोत्सव का चन्द्रमा वैसे तो अपनी 16 कलाओं के साथ चमकने की मान्यता के साथ चमकीला माना ही जाता रहा है, लेकिन इस बार वैज्ञानिक रूप से 17 अक्टूबर, गुरुवार को उदित होने वाला चंद्रमा शरद सुपरमून के रूप में साल का सबसे चमकीला चंद्रमा था।

विज्ञान संचारिका और नेशनल अवार्ड विनर विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि चमकता चंद्रमा, पृथ्वी से मात्र 3 लाख 57 हजार 3 सौ 64 किमी की दूरी पर रहेगा जो कि इस साल के लिए सबसे कम दूरी है। नजदीकियों के कारण यह अपेक्षाकृत बड़ा और चमकदार दिखेगा। पश्चिमी देशों में इसे हंटर्स मून का नाम दिया गया है ।

इस समय आएगा सबसे निकट बिंदु

भारत के समयानुसार दोपहर 4 बजकर 56 मिनट पर यह सबसे निकट बिंदु पर आएगा और इसके लगभग 1 घंटे बाद ही यह पूर्व दिशा में शरद सुपरमून के रूप में उदित होकर रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप बुधवार रात ही खीर खाकर उत्सव मना रहे हों लेकिन चमक के मामले में तो वैज्ञानिक रूप से गुरुवार को ही चंद्रमा की चमक अधिकतम थी।

सीएम 28 अक्टूबर को करेंगे सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू

पीएम मातृ वंदन योजना में सबसे ज्यादा शिकायतें बाकी, कुल 7.31 लाख कम्प्लेंट पेंडिंग

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में आम जन की शिकायतें सुनने और उसके त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन में कम्प्लेंट का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अब तक 7.31 लाख से अधिक शिकायतें हेल्पलाइन में पेंडिंग हैं। जिसमें से 3.39 लाख कम्प्लेंट सरकार द्वारा तय की गई सौ दिन की टाइम लिमिट पार कर चुकी हैं। इन हालातों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री मोहन यादव 28 अक्टूबर को कलेक्टरों के साथ समाधान ऑनलाइन के दौरान सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने वाले हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की कम्प्लेंट के निराकरण में हो रही देरी पर सभी विभाग प्रमुखों व कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसमें तेजी लाने के लिए कहा है। प्रमुख सचिव ने खास तौर पर सौ दिन की टाइम लिमिट में शिकायतों के निराकरण पर फोकस किया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुए समाधान आन लाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा की जाती रही है। मोहन सरकार बनने के बाद सीएम यादव ने इस ऑनलाइन बैठक पर ज्यादा फोकस नहीं किया लेकिन उन्होंने औचक निरीक्षण कर सीएम हेल्पलाइन काल सेंटर पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से बातचीत जरूर की। अब शिकायतों के निराकरण में हो रही देरी पर सीएम कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के काम में कसावट लाने के लिए ऑनलाइन रिव्यू करने वाले हैं।